RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

16-31 जूलाई, 2018

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 2/ पृष्ठः 16

www.therievtimes.com

सहयोगात्मक विकास के क्षेत्र में आईआईआरडी ने भरा रिक्त स्थान... बी के अग्रवाल

रीव टेलीमेडिसन ...घर से जांच, घर तक उपचार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन रीव की अद्वितीय पहल

रीव टीम, शिमला (हेम चौहान)

जन स्वास्थ्य एवं सुगम, सुलभ व सस्ता उपचार की प्राथमिकता पर केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मिशन रीव ने जनऔषधि केन्द्रों को पूरे हिमाचल में लोगों तक पहुंचाने तथा अपनी ही तरह की पृथक एवं नई पहल टेली मेडिसन को जन–जन तक अति सरल व ऑनलाईन स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु आरम्भ किया है । इसे विश्वस्तरीय अद्वितीय पहल इसलिए भी कहा जा रहा हैं क्योंकि अभी तक इस प्रकार की पहल से सीधा लोगों को उनके घरों में प्राथमिक जांच से लेकर उपचार और औषधी वितरण तक का कार्य किया जा रहा हैं ।

यहां समझे लॉगइन करने की प्रक्रिया

टेलिमेडीसन प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल में कोई भी पंजीकृत चिकित्सक अपना पंजीकरण करवा सकता हैं । इसके लिए डॉक्टर को वेबपोर्टल (www.telemedicine.missionriev.in) पर लॉगइन कर अपना पंजीकरण समस्त दस्तावेज़ी औपचारिकताओं एवं प्रमाणिकता के साथ करना हैं । चिकित्सक के पंजीकरण की पुष्टि मिशन रीव सचिवालय से की जाती है तथा उन्हें आईडी दी जाती हैं । उसके बाद गावं–गांव में स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से लोगों की जांच का सारा विवरण स्वास्थ्य मोबाईल लैब में जाता हैं और स्वास्थ्य मोबाईल लैब में जांच के उपरांत रिपोर्ट उसी वेबपोर्टल पर डॉक्टर के पास स्वतः रिकॉर्ड में आ जाता हैं । जैसे ही डॉक्टर अपनी आईडी से लॉग इन करते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूरा विवरण पोर्टल पर आ जाता हैं जो कि स्वास्थ्य लैब के अंतर्गत किया गया था ।

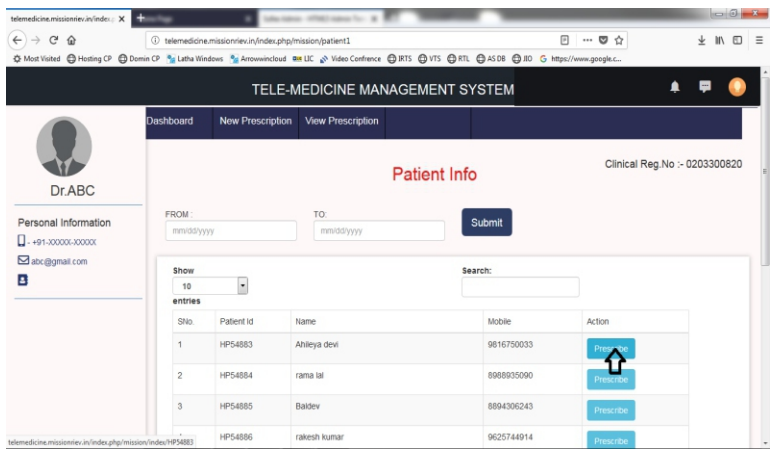

यहां देखी जा सकेगी पेशेंट हिस्ट्री

डॉक्टर जांच के परिणामों का अध्ययन कर आगामी चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार हेतु ऑन लाइन प्रक्रिया को अपनाता हैं यानि व्यक्ति की जांच के परिणामों में यदि उसे उपचार की आवश्यकता हैं और कोई दवाई देनी हैं तो संस्था के पोर्टल पर ही सारी दवाइयों का विवरण उपलब्ध हैं। डॉक्टर द्वारा एक क्लिक पर ही संबन्धित दवाईयों को निर्धारित कर चयनित कर लिया जाता हैं । पोर्टल पर ही दवाईयों को किस प्रकार और कितने समय में लेना हैं, क्या खाना है , क्या परहेज़ करना है, यह डाइटचार्ट आदि डॉक्टर ऑनलाइन ही भरेंगें ।

एक क्लिक पर ही दवाईयों की लिस्ट

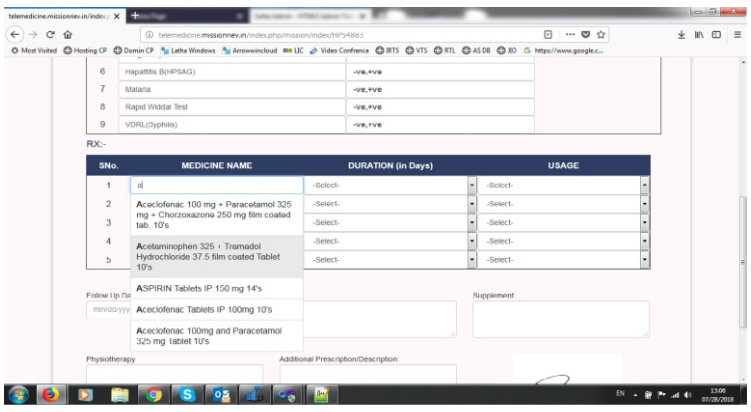

पोर्टल पर समस्त दवाईयां मात्र एक क्लिक से ही देखी और मरीज़ को लिखी जा सकती हैं । ये सभी दवाईयां जेनेरिक हैं व अन्य किसी भी ब्रांड की दवाइयों से दाम कम हैं और मिशन रीव द्वारा संचालित जेनेरिक औषधी केन्द्रों पर सुगमता से उपलब्ध है । सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसकी ऑनलाईन प्रमाणित प्रति मोबाईल लैब, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, ज़िला कॉर्डिनेटर और पंचायत फेसिलिटेटर के पास भी उपलब्ध हो जाती है । जांच और डॉक्टर के परामर्श एवं देखरेख के बाद रीव पंचायत फेसिलिटेटर संबन्धित व्यक्ति के पास जाकर उसे डॉक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं उपचार की जानकारी घर पर ही देते हैं । रीव के जनऔषधि केन्द्रों से सस्ती दवाईयों को उपलब्ध करवा कर उपचार आरम्भ हो जाता हैं तथा समस्त चिकित्सिय सलाह और जानकारी का लिखित प्रतिलिपि मरीज़ को दी जाती हैं ।

एक निर्धारित समय के बाद डॉक्टर मरीज़ के उपचार की देखरेख ऑनलाईन ही करते हैं क्योंकि 10 या 15 दिनों के बाद पुनः स्वास्थ्य सेवक मरीज़ की जांच करते हैं । डॉक्टर को इसकी पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ऑनलाईन परामर्श देने की सुविधा हो जाती हैं । यदि मरीज़ को दवाईयों के अलावा भी बीमारी की बढ़ रही गंभीरता से दो–चार होना पड़ रहा हैं और उसे उपचार और गहन व विस्तृत जांच की आवश्यकता हैं तो डॉक्टर राज्य अस्पतालों के लिए भेजने का परामर्श देते हैं ।

यहां गौरतलब यह है कि इस प्रकार की यह अपने आप में अद्वितीय पहल है जो अभी तक पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं चलाई जा रही हैं । हालांकि टेलीमेडिसन के कुछ प्रारुप देश में चल रहे हैं किंतु उसका दायरा कुछ भागों में ही सीमित हो जाता हैं और वह प्रक्रिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्त प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं करता है । जबकि मिशन रीव की टेली मेडिसन सेवा एक इंसान को उसके घर से आरंभिक जांच करते हुए मोबाईल लैब की जांच प्रक्रियाओं और फिर डॉक्टर की सलाह, परामर्श एवं उपचार की प्रमाणिकताओं को पूरा करते हुए वापिस स्वास्थ्य सेवकों द्वारा उस इंसान के घर पर ही जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता के साथ इस सेवा को अन्य सेवाओं से पृथक करती हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी आम इंसान को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पाई हैं। सरकार अपने स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ समय–समय पर लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करती है किंतु धरातल पर एक भी ऐसी योजना अभी तक सफल होती नहीं नज़र आ रही जिससे साधारण इंसान स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के साथ आगे बढ़ सके । हालांकि मोदी सरकार स्वास्थ्य कार्ड की योजना को बहुत हद तक आम लोगों विशेष तौर पर ग़रीब तबके को राहत की गारंटी के साथ सामने आई है किंतु सत्य तो यह भी है कि धन की उपलब्धता को संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता है ।

पीड़ा के बढ़ जाने पर अंततः चैकअप करवाने पर काफी नुकसान हो जाता हैं । शहर के अस्पतालों के चक्कर और महंगी जांच लैब में आदमी पिस कर रह जाता हैं । ऐसे में स्वास्थ्य को खतरे के ज़ोन में डालकर स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड की सहायता तो मिल जाएगी पर हो चुके स्वास्थ्य नुकसान की भरपाई में समय लग जाता हैं और कभी–कभार तो पूर्ति करना ही मुश्किल हो जाता है ।

क्या कहते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य बी के अग्रवाल

मिशन रीव के तहत जनऔषधि केन्द्र शिमला का उद्घाटन करने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बी के अग्रवाल ने बताया कि जनऔषधि केन्द्रों के खुलने से गांव में लोगों को सस्ती एवं गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध हो पाएगी, जिसमें आईआईआरडी ने प्रशंसनीय कार्य किया है । उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऐसी संस्था की कमी लंबे समय तक देखी गई जो योजनाओं को धरातल पर लागु करने और नए प्रयासों के साथ सामने आए । प्रदेश में इस कमी को आईआईआरडी ने पूरा किया हैं । जनऔषधि केन्द्रों के संचालन एवं अन्य औपचारिकताओं में सरकार संस्था को सहयोग करेगी । इससे न केवल सेवाओं की सुलभता आम जनता को होगी बल्कि संस्था के रोजगार के लक्ष्य से प्रदेश की आर्थिकी में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा ।

जनऔषधि केन्द्र : गुणवत्ता एवं कीमत आम आदमी की पहुंच में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम जन के लिए सस्ती एवं आम आदमी की पहुंच में दवाईयों को लाने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोलने की सार्थक पहल की हैं । विडंबना तो ये भी है कि अभी गांव में एक बड़ी प्रतिशतता में ऐसी आबादी भी हैं जो जेनेरिक का मतलब ही नहीं जानती हैं और न ही इस बेहद उपयोगी योजना की कोई जानकारी उन तक सही तरीके से पंहुच पा रही हैं । इतना ही नहीं , स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पंचायतें यदि लोगों से संपर्क कर भी रही हैं तो इसमें बहुतेरों को राजनीति की पृष्टभूमि भी दिखाई दे रही हैं । इस योजना को हमारे बहुत से ग्रामीण प्रतिनिधि अपनी योजना बताकर चुनावों की गोटियां फिट करते हैं और इसके मूल उद्देश्यों को लोगों को ठीक प्रकार से नहीं बता पा रहे हैं ।

गांव में एक व्यक्ति को जब पूछा गया कि जेनेरिक औषधि के बारे आप क्या जानते हो.. ....तो इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी उनके पास नहीं थी जबकि उनका स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए उनसे संपर्क किया जा चुका था । उन्हें तो मात्र इतना बताया गया कि यह कार्ड पंचायत आपको बना रही है और आपका इलाज़ इसमें सस्ता और निशुल्क होगा ।

ब्रांडेड व जेनेरिक दवाईयों की गुणवत्ता एवं कीमतों का अंतर

Name of Salt	Dosage	Pack	Average Market Price of Branded Medicines(Rs.)	Prices of Generic Medicines sold in JanAushadhi generic drug stores (Rs.)
Ciprofloxacin	250 mg	10	55.00	11.10
Ciprofloxacin	500 mg	10	97.00	21.50
Diclofenac SR	100 mg	10	51.91	3.35
Cetrizine	10 mg	10	37.50	2.75
Paracetamol	500 mg	10	13.56	2.45
Nimesulide	100 mg	10	38.66	2.70
Cough Syrup		110ml bottle	33.00	13.30

शेष पेज 7 पर...

मिशन रीव की सदस्यता.....एक परिचय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव बढ़ते क़दमों के साथ जनमानस की आकांक्षाओं और विश्वास को हासिल करता हुआ नित नई उंचाईयों को छू रहा है । मिशन की सभी सेवाओं को धीरे–धीरे लोगों के साथ संबद्ध कर गांव में पहुंचाने का प्रयास हरसंभव सुनिश्चित बनाया जा रहा है । मिशन रीव के सदस्यों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सभी सेवाओं की उपलब्धता सहज करने के लिए रीव के स्वयंसेवी तत्पर हैं । किंतु सभी सेवाओं का लाभ लेने एवं मिशन रीव से जुड़ने का आरंभिक चरण सदस्यता से होता हैं । सर्वप्रथम मिशन रीव के सदस्य बनाए जाते हैं और उसके बाद आवश्यकता आधारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता हैं ।

सदस्यता के लिए पूर्व में तो सभी के लिए एक समयसीमा के अंदर विकल्प खुले रखे गए थे किंतु समयावधि समाप्त होने के बाद सदस्यता लेने की प्रक्रिया में कुछ आमूलचूक परिवर्तन किए गए हैं ।

कैसे बनें मिशन रीव के सदस्य

सदस्य बनने के लिए दो विकल्प रहते हैं । एक ऑनलाईन और एक ऑफलाईन । ऑनलाईन प्रक्रिया में मिशन रीव के फेसिलिटेटर गांव में लोगों से संपर्क करते हैं और इसके लिए एंपलॉय की एक आईडी जारी की गई हैं । इसी आईडी के तहत ऑनलाईन सदस्यता फॉर्म भरा जाता हैं । इसके लिए सबसे पहले वेबपोर्टल (http//missionriev.in) पर लॉगइन कर एंमलॉय पोर्टल पर जाकर कोई भी स्टाफ सदस्य जिसे आईआईआरडी द्वारा आईडी एवं पासवर्ड जारी किया गया हैं, उसका उपयोग कर सकता हैं । लॉग इन के बाद मेंबरशिप पर क्लिक करें। मैम्बर आईडी पर जाकर सदस्यता फॉर्म खुलता हैं । उस फॉर्म को ऑन लाईन ही भरना हैं और इसमें जो बिन्दु अतिआवश्यक हैं उन्हें भरना अनिवार्य हैं ।

सदस्यता में परिवार की परिभाषा

सदस्यता फॉर्म भरने के बाद परिवार का कॉलम आता हैं जिसे यहां समझने की आवश्यकता हैं । सदस्य बनने के बाद उस व्यक्ति का परिवार भी मिशन रीव की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए चयनित हो जाता हैं । उस व्यक्ति के परिवार की परिभाषा उसके राशन कार्ड के सदस्यों पर आधारित हैं । यानि राशन कार्ड में जितने सदस्य होंगें, वो सब सदस्यता की श्रेणी में आते हैं और मिशन रीव की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता रखते हैं । परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण विवरण वांछित आंकड़ों के साथ भरा जाता हैं ।

सदस्यता फीस

सदस्यता फॉर्म भरने के बाद मिशन रीव की सदस्यता फीस ऑनलाईन भरी जाती है । सदस्यता फीस 2000/– रुपये हैं जिसे ऑनलाईन भरा जाता हैं । सदस्य फीस अदायगी के किसी भी प्रारुप को अपना कर जमा करवा सकता हैं जैसे कि एटीएम, ऑनलाईन मोड़, पेटीएम आदि ।

यहां गौर करने की बात ये है कि इस सदस्यता फीस में सदस्य का पूरा परिवार लाभार्थी हो जाता है और मिशन रीव की समस्त सेवाऐं पूरे परिवार को इसी फीस के दायरे में प्राप्त हो जाती हैं । उदाहरण के लिए सदस्य के परिवार में कुल पांच लोग हैं । तो सदस्य की फीस के गणित में प्रत्येक सदस्य को 400/–रुपये में रीव की सेवाऐं प्राप्त हो रही है .....यह अब तक की सबसे सस्ती और विश्वसनीय सेवा हिमाचल प्रदेश में कही जा सकती हैं ।

सदस्य बनने के बाद मेल अथवा अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी प्रतिलिपि सदस्य को दी जाती हैं । साथ ही एक प्रतिलिपि रिकॉर्ड के लिए सदस्य को दी जाती हैं और एक रीव सचिवालय के रिकॉर्ड में आ जाती हैं ।

हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरदराज के ज़िलों में नेटवर्क सेवाओं के कमज़ोर होने के कारण ऑनलाईन फॉर्म भरने और सदस्यता लेने में दिक्कत आती हैं । इसके लिए कभी–कभार ऑफलाईन फार्म भी भरने पड़ते हैं । इसके लिए आईआईआरडी के स्वंयसेवी घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद मिशन रीव सचिवालय में फीस को ऑनलाइन मोड़ में जमा कर उस सदस्य की ऑनलाईन आईडी बनाई जाती हैं ।

आवश्यकता आधारित आकलन

सदस्य बनने के बाद की प्रक्रिया में सर्वप्रथम उस परिवार की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता हैं । साधारणतया उस परिवार की क्या ज़रुरतें हैं, इस का आकलन ऑनलाईन ही किया जाता हैं । हमारी समस्त सेवाऐं ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध हैं तथा बुकलेट आदि में भी लिखित मेटिरियल सदस्य को उपलब्ध करवाया जाता हैं । सदस्य अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करके मिशन रीव को चिन्हित करता हैं और उन सेवाओं की शर्तों पर मिशन रीव से जुड़ता हैं । सेवाओं को चिन्हित करने के बाद उसका प्राथमिकीकरण किया जाता हैं यादि सबसे अहम और आवश्यक कार्य कौन सा हैं जिसकी सदस्य को आवश्यकता हैं , इस पर चर्चा कर इसे अंतिम रुप दिया जाता हैं । समस्याओं का प्राथमिकीकरण करने के बाद उन सेवाओं के दाम जो कि पूर्व निधारित हैं, तय किये जाते हैं और मिशन रीव के स्वयंसेवी समस्याओं के निदान के लिए कार्य आरम्भ करते हैं ।

मिशन रीव की जनहित सेवाऐं

अंततः यह जानना अतिआवश्यक हैं कि मिशन रीव जिन उद्देश्यों के साथ लोगों के मध्य हैं वों कौन–कौन सी सेवाऐं हैं और किस प्रकार लोग गांव में इससे जुड़कर इसका लाभ लेते हैं । मिशन रीव लगभग प्रत्येक क्षेत्र से संबन्धित सेवाओं के लिए समर्पित हैं । इसमें स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, कला–कौशल आदि प्रत्येक क्षेत्र में मिशन रीव सेवार्थ उपलब्ध हैं । मिशन रीव ने हर संभव प्रयास यही किया है कि लोग अपने अनमोल समय को छोटी–बड़ी समस्याओं में न खपाकर, उस समय का सदुपयोग अपने सूचीबद्ध कार्यों में लगाए तथा अपनी ही समस्या को मिशन रीव के कांधों पर डालकर सुनिश्चित हो जाए । 'आवश्यकताऐं आपकी–सेवाऐं हमारी' इस मूलमंत्र के साथ मिशन रीव आपके साथ हर क्षण खड़ा है।

उपरोक्त सेवाओं के लिए परिवार में भी समस्या की प्राथमिकता को देखा जाता हैं । यदि परिवार के मुखिया को कृषि उपकरण की आवश्यकता हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य को करियर काउंसलिंग की आवश्यकता हैं तो उसमें जिस समस्या को अधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक किया जाऐगा, उस कार्य को मिशन रीव के स्वयंसेवी पहले करेंगें और उसके बाद दूसरा कार्य । इसी प्रारुप को पूरे प्रदेश में सभी सदस्यों के साथ अपनाया जाता हैं ।

मिशन रीव - सेवा क्षेत्र

मुख्यतः नौ क्षेत्रों में सेवाओं का वितरण किया गया हैं जिसमें सभी समस्याओं का निदान विस्तारित हैं ।

- कृषि एवं बागवानी
- बैंकिंग क्षेत्र
- शिक्षा एवं रोजगार
- आपातकालीन सेवाऐं
- उद्यमिता/व्यवसाय क्षेत्र में सेवाऐं
- स्वास्थ्य सेवाऐं
- लाईसेंस एवं प्रमाणपत्र
- ऑनलाईन सेवाऐं

प्रदेश में सदस्यता आंकड़ा

वर्तमान में मिशन रीव प्रदेश के 12 ज़िलों के सभी विकास खण्डों में सेवाऐं दे रहा हैं तथा यही प्रयास हैं कि प्रदेश की सभी पंचायतों को अब इसमें शामिल कर लिया जाऐगा । सदस्यता का आंकड़ा 5000 के लगभग हो चुका हैं तथा इसे अब जन अभियान बनाया जा रहा हैं और भविष्य में इसे सभी लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य हैं । हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िलों में मिशन रीव में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या ज़िला शिमला और ज़िला ऊना में हुई हैं । इसके अलावा कांगड़ा, किन्नौर आदि ज़िलों में भी रीव की सेवाओं के लिए सदस्यता हेतु लोगों में खासा उत्साह हैं और सदस्यों की संख्या में निरंतर बढ़ौतरी हो रही हैं ।

मिशन रीव के सदस्य बने सम्माननीय शक्सियतें

भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरण नेगी ने मिशन रीव की सदस्यता ली, अंतर्राष्ट्रीय कब्डडी खिलाड़ी अजय ठाकुर के अलावा हर क्षेत्र की सम्माननीय शक्सियतें भी मिशन रीव की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं ।

सदस्यता उपरांत आंतरिक एवं बाह्य सेवाऐं

मिशन रीव के तहत दो प्रकार की सेवाओं को सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया हैं । आंतरिक सेवाओं में लोगों के उन सभी कार्यों को रीव की टीम पूरा करेगी जो उन्होंने आवश्यकता आधारित आकलन में चिन्हित की हैं । यानि उनके जीवन से जुड़ें हर छोटे बड़े काम इसमें शामिल हैं । कार्यानुसार निर्धारित फीस की अदायगी की जाती हैं । वहीं बाह्य सेवाओं में भी मिशन रीव अनेक प्रकार की सेवाओं के साथ लोगों के मध्य में पहुच चुका हैं । जिनमें स्वास्थ्य स्लेट, मोबाईल लैब, जेनरिक औषधि केन्द्र, जेनरिक दवाईयों की उपलब्धता, मिट्टी जांच परीक्षण, जैविक खाद, जैविक स्प्रे आदि शामिल हैं ।

सदस्यता फार्म एवं शर्तें

MISSION RIEV

Ruralising India- Empowering Villages

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर

कि दुनिया देखती रह जाए

A People Centric Collaborative Initiative of IFSD, IFTI, FGPL, HSS & HDBNL under Umbrella of IIRD Shimla

MEMBERSHIP FORM

सदस्यता फार्म

Membership ID/ सदस्यता नंबर

आवेदक का नाम Applicant Name	
पिता/पति का नाम Father / Husband Name	
जन्मतिथि DOB (D D M M Y Y Y Y)	लिंग Gender (M F O)
पता Address	
शैक्षणिक योग्यता /Educational Qualifications	आधार नंबर Aadhaar No.

परिवार के सदस्यों के विवरण / Particulars of Family members

नाम Name	आवेदक से संबंध Relation with Member	जन्मतिथि DOB	शैक्षणिक योग्यता Qualification	ईमेल आई डी Email ID	फोन नंबर Contact No.	आधार नंबर Aadhaar No.

घोषणा: मैं स्वेच्छा से घोषित और पूरी तरह से समझता हूं कि मिशन रीव का सदस्य होने के नाते, अनुलग्न–I के अनुसार और जब जरूरत पड़ने पर मिशन के सीमित दायरे मैं मेरे परिवार को विभिन्न ज्ञानात्मक सूचनात्मक और कौशल आधारित लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं । तथा अनुलग्नक –II के अनुसार मैं सदस्यता की शर्तों का पालन करता हूँगा ।

Declaration: I solemnly declare & fully understand that being member of Mission RIEV, my family will be privileged to seek various promotional, informatory and skill based benefits as and when needed or sought for within the limited purview of the Mission as per annexure I and shall abide by the membership terms and conditions of the Mission as per annexure II.

सदस्यता शुल्क के लिए 2000/– रूपए (केवल दो हजार रूपए) की राशि को मैं प्रसन्नता पूर्वक अदा करता हूँ ।

I am glad to remit a sum of rupees 2000/-(Rupees two thousands only) towards membership fee.

स्थान/Place.....

तिथि/Date.....

हस्ताक्षर / Signature

कि दुनिया देखती रह जाए

Terms and conditions

The membership will be governed by the following terms and conditions

1 मात्र यह फॉर्म भरकर सदस्यता के लिए आवेदन करने से सदस्यता की गारंटी नहीं मिलती है । निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा किये जाने पर टीम मिशन रीव द्वारा उपयुक्त स्तर पर स्वीकृत प्रदान की जाएगी ।
That merely applying for membership by filling the form does not guarantee the membership until prescribed membership fee is deposited and approval is conveyed by the Team Mission RIEV at appropriate level.

2 यह सदस्यता पति–पत्नी, बच्चों और माता–पिता सहित पूरे परिवार के लिए लागू होगी और परिवार केवल राशन कार्ड के अनुसार ही माना जाएगा । राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
That this membership shall be applicable for entire family comprising spouse, children & parents and shall be considered as per ration card only. (copy to be enclosed)

3 यह सदस्यता स्वयं ही सभी नियमों, शर्तों का पालन करने और मिशन व इसके संचालन की प्रक्रियाएं के लिए सदस्यों की ओर से स्वीकृति की पुष्टि है ।
That the membership itself is the confirmation of the member to abide by all the terms, conditions and procedures of the Mission and its operations.

4 सदस्य को कभी भी समयसीमा के भीतर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने का विशेषाधिकार होगा और यह "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर होगा ।
That the member shall have privilege to avail various services available at any point of time within the framework and shall be on "First Come First Serve" basis.

5 सदस्यता आवेदन अवधि हर साल नवंबर और दिसंबर महीनों में निर्धारित सदस्यता शुल्क रू. 2000/– केवल दो हजार रूपये में होगा । और सदस्यता की वैधता 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगी । हालांकि, मिशन जनवरी से मार्च तक देर शुल्क के साथ सदस्यता आवेदन स्वीकार कर सकता है । सदस्यता आवेदन अप्रैल से हर अक्टूबर तक बंद किए जाएंगे ।
That the membership application period shall be Nov & Dec every year with the prescribed membership fee of Rs. 2000/- (Rs. Two Thousand Only) and the validity of membership for one year starting from 1st January and ending on 31st December every year. However, the Mission may accept the membership applications with late fee from January to March or as notified. Membership applications shall be closed from April to October every.

6 यह सदस्यता वार्षिक आधार पर होगी और इसे 31 दिसंबर या इस से पहले नवीनीकरण करने पर ही अगले वर्ष जारी रखा जाएगा ।
That the membership shall be on annual basis and shall be continued subject to renewal on or before 31st Dec. of the preceding year.

7 अनुलग्न I में उल्लिखित सेवाऐं संसाधनों की उपलब्धता, स्रोत और पात्रता की शर्तों और उसी अवधि जिसके लिए आवेदन किया है, के अनुसार लागू होगी ।
That the services as mentioned in the annexure I shall be subject to availability of resources, applicability from the source and eligibility conditions as be applicable during the period of applying for the same.

8 सेवाओं की मात्रा, परिमाण और आवृत्ति, विवेकपूर्ण आवश्यकताओं,संसाधनों की उपलब्धता और सेवाओं का लाभ लेने के लिए सदस्यों के प्रयासों में निरंतरता या मिशन के नियन्त्रण से परे अन्य कारक पर निर्भर करेगी ।
That the quantum, magnitude and frequency of the services shall depend on the judicious needs, availability of resources and consistency in members' efforts to avail the services or any other factor beyond the control of the Mission.

9 एक बार भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी मामले में वापसी योग्य नहीं होगा ।
That the membership fee once paid shall not be refundable in any case.

10 सदस्य का मिशन के विभिन्न सेवा उत्पादों, संचालनात्मक प्रक्रियों को समझने, अपनी राय या सुझाव देने तथा मिशन के विभिन्न मंचों में सक्रिय भागीदारी का विशेषाधिकार होगा तथा मिशन की परिभाषित सीमाओं के अधीन मिशन के प्रबन्धन दल का हिस्सा माना जाएगा ।
That the member shall have privilege to understand different service products, procedural steps, share opinions and suggestions and avail opportunities of active participation in different forums under Mission RIEV; hence shall be treated the part of the management team within the defined jurisdiction of the Mission.

11 सदस्य बनना, व्यक्ति या परिवार का, बिना किसी स्वार्थ के मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया स्वैच्छिक कार्य है तथा एक वर्ष बाद इसका नवीकरण करना या नहीं, व्यक्ति की ईच्छा पर निर्भर करेगा ।
That becoming member is a voluntary action of the individual or the family to support and promote the objectives of the Mission without any expectations whatsoever in return and the member shall have the option whether to renew the membership after one year or not.

12 व्यक्तिगत या परिवार का सदस्य होने के नाते, मिशन के लिए निरंतर सलाह और संरक्षण प्रदान करने का दायित्व होगा और किसी भी मामले में जो मिशन के कार्य, कृत्य या प्रगति की कार्यप्रणाली को रोकते हैं, में शामिल नहीं होंगे। सभी कानूनी जटिलताओं और कुकृत्यों से सदस्य मिशन के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है । हालांकि, सभी कानूनी मामलों का क्षेत्राधिकार केवल शिमला होगा
That being member, the individual or family shall have the obligation to keep on providing constant mentoring support and patronage to the Mission and in no case shall get involved in any kinds of the act, deed or action which hampers the progress and smooth functioning of the Mission. The member commits to safeguard the interest of the Mission from all legal complications and to be abstained from litigations; however, all the legal matters shall be subject to Shimla jurisdiction only.

13 मिशन की ज्ञानात्मक, सूचनात्मक, कौशलात्मक तथा तकनीक आधारित निःशुल्क सेवाओं को उपयोग का सदस्य के पास "पहले आओ पहले पाओ" पर आधारित विशेषाधिकार रहेगा, साथ ही जिन सेवाओं में अधिक गहनता होगी, इनका शुल्क समयानुसार निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा ।
That the member shall have the privileges to avail complementary services of technical support nature to bridge the gaps on information, knowledge, skills & technology from the Panchayat Facilitators or other Mission functionaries on "First Come First Serve Basis"; the higher as well as deeper interventions of services shall attract different unit prices as be applicable from time to time.

14 सदस्यों को सरकार में या अन्य संगठन में आवेदन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान अतिरिक्त करना होगा ।
The members will have to pay the charges for the process of application in Govt. or other organisation as per applicability separately.

15 सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा
Members shall be responsible for the information provided by them.

16 भविष्य में सदस्य को सुचना दिए बिना नियम और शर्तों सहित सदस्यता में परिवर्तन या गुणात्मक संशोधन, कुछ जोड़ने और हटाने के लिए सदस्य की सहमती होगी । सभी उद्देश्यों के लिए मिशन प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।
.All the addition, deletion, modification, alteration or value addition in the modalities of the membership including terms & conditions in future, if any, shall be agreeable to the member with or without notification. The decision of the Mission Management shall be final and binding on all for all purposes.

17 सरकार या अन्य संगठन द्वारा आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी देरी के लिए आईआईआरडी जिम्मेदार नहीं होगा। और गुणवत्ता और निष्पादन के संबंध में किसी भी विवाद के कारण मिशन रीव प्रबंधन और / या कोई भी यहां दिए गए नियमों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन और किसी भी हानि, क्षति, दावों, लागतों और खर्चों के विरुद्ध जो खर्च किया जा सकता है सदस्य मिशन प्रबंधन की क्षतिपूर्ति करेगा ।
IIRD shall not be responsible for any delay in the process of application by Govt. or other organisation. And the member shall indemnify and keep indemnified the Mission Management against any loss, damage, claims, costs and expenses which may be incurred or suffered by Mission RIEV Management due to any disputes in respect of quality and performance and / or any breach of any of the terms and conditions herein contained.

तिथि/Date.....

हस्ताक्षर/Signature.....

मिशन रीव के तहत प्रदेश में दो लाख किलो जैविक खाद तैयार

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

टीम रीव, शिमला

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में आईआईआरडी ने मिशन रीव के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं। पिछले महज दो माह के दौरान प्रदेश के दो जिलों में ही विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर मिशन रीव के तहत दो लाख किलो जैविक खाद का भंडार तैयार किया गया है। जिला शिमला में करीब 50 हजार और जिला सोलन में डेढ़ लाख किलो खाद तैयार की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और उनसे खरीदकर मिशन रीव के तहत उन्हें खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है।

यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

निशुल्क प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने से मजबूत हुई किसानों की आर्थिकी

संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आईआईआरडी के बीडीएम एग्रीकल्चर हरीश कहते हैं कि हिमाचल में खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर जैविक खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की आर्थिक को मजबूत किया जा सकता है। जब गांव में जाकर लोगों से बात की गई तो वह जैविक खेती को लेकर काफी उत्साहित थे। जब उन्हें रासायनिक खादों से भूमि के साथ–साथ स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया गया तो सौ फीसदी जैविक खेती को ही अपनाने के पक्ष में थे।

जैविक खेती के लाभ

कृषकों की दृष्टि से लाभ

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।

मिट्टी की दृष्टि से

- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से

- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

ग्रामीणों की आवाज बनेगा द रीव टाइम्स

लॉच हुआ समाचार पत्र का पहला संस्करण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर आईआईआरडी के मिशन रीव में उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया जब 15 जुलाई को आईआईआरडी ने द रीव टाइम्स पाक्षिक समाचार पत्र का पहला संस्करण बाजार में उतारा। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बीके अग्रवाल विशेष तोर पर मौजूद रहे। प्रदेश में कई बड़े समाचार पत्रों की दुनिया से अलग हटकर द रीव टाइम्स की शुरूआत खासतौर पर ग्रामीणों की आवाज उठाने के लिए की गई है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का एक मज़बूत स्तंभ है और उम्मीद है कि द रीव टाइम्स इसमें जनभावनाओं और उनकी समस्याओं को शामिल कर उन्हें उचित स्थान देगा।

द रीव टाइम्स के मुख्य संपादक डाक्टर एलसी शर्मा के अनुसार इस समाचार पत्र में देश दुनिया से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही हिमाचल के गांवों की समस्या को उठाने और उनका समाधान कराने पर फोकस रहेगा।

द रीव टाइम्स के संपादक आनंद नायर ने समाचार पत्र की लॉचिंग पर इसे एक क्रांतिकारी क़दम बताया।

सरला के लिए जीवन रक्षक बना मिशन रीव

जब किसी से उम्मीद नहीं थी तब घर पहुंचाई मदद

टीम रीव, किन्नौर

उस दिन मौसम बेहद खराब था। लगातार बारिश से रास्ता टूट गया था। ऐसे में अस्पताल पहुंचना नामुनकिन था। किन्नौर के कल्पा ब्लॉक की थेमंगरंग पंचायत सरला की तबीयत डिहाइड्रेशन के कारण लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब डाक्टर से किसी तरह संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत मरीज को ड्रिप लगाने की सलाह दी। लेकिन खराब मौसम के बीच ड्रिप घर तक लाना किसी चुनौति से कम नहीं था। ऐसे में मिशन रीव के प्रतिनिधी अजेंद्र ने जब सरला के घर ड्रिप पहुंचाई तो कहीं जाकर सरला के परिवार ने राहत की सांस ली।

सरला ने ठीक होने के बाद मिशन रीव के साथ अपने अनुभव को कुछ इस तरह साझा किया, मुझे तो लग रहा था कि मैं अब एक महीना बिस्तर से नहीं उठ नहीं पाउंगी। मौसम खराब होने के कारण रास्ता टूट गया तो अस्पताल जाना भी मुश्किल था। लेकिन जब अजेंद्र ने ड्रिप का इंतजाम घर पर ही कर दिया तो मेरी जान में जान आई। अब में ठीक हूं और मिशन रीव का धन्यवाद करती हूं कि जब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तो मिशन रीव के प्रतिनिधि अजेंद्र ने हमारी सहायता की।

अब आयस्टर मशरूम से बदलेगी किसानों की आर्थिकी:

आईआईआरडी शिमला में पायलैट प्रोजेक्ट सफल

टीम रीव, शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरूखी और जंगली जानवरों की समस्या ने किसानों की कमर तोड़ दी हैं। हालात ये है कि किसान अपनी जमीन बंजर छोड़ने को मजबूर है। बागवानी में भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। ऐसे में किसानों और बागवानों की आर्थिकी लगातर कमजोर हो रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला ने मिशन रीव के माध्यम से कमजोर होती आर्थिकी को मजबूत करने की मुहिम शुरू की हैं। इसके तहत गांवों में जाकर लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अगर कोई मशरूम लगाना चाहता है तो उसके लिए निशुल्क प्रशिक्षण देकर बाजार उपलब्ध कराने की सुविधा भी मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही है।

इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी शिमला कार्यालय में जुलाई माह के पहले सप्ताह में पायलैट प्रोजेक्ट के तौर पर मशरूम प्लांट स्थापित किया गया था। सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा है। इस प्लांट के बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं और यहां ऑयस्टर का उत्पादन भी शुरू हो गया है। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि मिशन रीव के तहत पंचायतों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ऑयस्टर मशरूम की खेती से जोड़कर गांवों की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

लौहाल-स्पीति में लोगों को किया जागरूक

टीम रीव, लौहाल-स्पीति

मिशन रीव लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उन्हें उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहा है जो सरकार की ओर से खास तौर उनके लिए बनाई गई है। इस बात को सरकारी अधिकारी भी मानतें है कि जानकारी के अभाव में अधिकतर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस खाई को पाटने के लिए लाहौल स्पीति के दूर दराज के गांवों में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से विशेश तौर पर गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत काजा ब्लॉक में भी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मिशन रीव के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, मिट्टी जांच परीक्षण व अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही काजा के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया

युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार के द्वार

टीम रीव, शिमला

आईआईआरडी में मिशन रीव के तहत पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार दिया जा राह है। इसी कड़ी में जिला शिमला के तहत विभिन्न पंचायत फेसिलिटेटर की नियुक्ति करने के लिए आईआईआरडी कार्यालय में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इसमें मशोबरा समेत अन्य ब्लॉक के बीस से अधिक युवाओं ने भाग लिया। वर्तमान में पूरे प्रदश में मिशन रीव के तहत तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। खासबात यह है कि युवाओं को अपनी ही पंचायत में रोजगार दिया जा रहा है और पंचायत के विकास में भी युवा अपना सहयोग दे रहे हैं। ब्लॉक कोआर्डीनेटर मशोबरा अंकुश नगरैक ने बताया कि मिशन रीव के तहत उनके ब्लॉक के तहत आने वाली पंचायतों में पंचायत फेसिलिटेर के तौर पर कार्य कर रहे युवा पंचायत में ही रोजगार मिलने से काफी खश है।

जुब्बल और छुहारा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

टीम रीव, शिमला

आईआईआरडी शिमला की ओर मिशन रीव के तहत प्रदेश के उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

इसी के तहत जुब्बल और छुहारा में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इस शिविर में सौ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसी तरह जिला के अन्य स्थानों पर भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच के साथ साथ ऑनलाइन रिपोर्ट भी जनरेट की जा रही है और लोगों को रिपोर्ट मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

लोगों का कहना है कि इन शिविरों से गांव के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। पहले टेस्ट कराने के लिए बाजार जाना पड़ता था। लेकिन अब गांव में ही टेस्ट होने से समय की बचत के साथ साथ समय पर स्वास्थ्य जांच भी हो रही है और लोग अपने स्वास्थ्य संबंधि परेशानियों को आसानी से पहचान कर उनका समय पर इलाज करा रहे हैं।

जुब्बल निवासी विरेन सारटा, रीता, महिमा व अन्य लोगों ने बताया कि रीव के तहत आयोजित शिविरों में एक साथ कई टेस्ट कराने की सुविधा होने से पैसे और समय की बचत के साथ ही आसानी से स्वास्थ्य लाभ गांव के लोगों तक पहुंच रहा है।

शिविरों में मोबाईल लैब से दो हजार से अधिक लोगों के रक्त की जांच की जा चुकी है। इसी तरह प्रदेश के दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें मिशन रीव के सदस्यों को निशुल्क सेवाएं दी गई।

बाजार जाने का झंझट खत्म, रोजमर्रा का सामान भी घर पर

टीम रीव, ऊना

प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी ऐसे कई गांव है जहां से शहर तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। इन गांव में लोगों को जरूरत का छोटा छोटा सामान घर तक पहुंचाने के लिए दो से तीन दिन लग जाते हैं। ऐसे में लोगों को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

लोगों की इन्हीं समस्याओं को सुलझाकर उनके जीवन को आसान बनाने की जिम्मेदारी मिशन रीव ने ली है।

मिशन के तहत लोगों को स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा क्रॉकरी व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

रीव घर तक पहुंचा रहा जरूरत का सामान

मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है। ऊना के थानाकलां निवासी कमलेश, रीना , सतरूखा के राकेश के मुताबिक मिशन रीव के जरिए वह रोजमर्रा की जरूरत का सामान आसानी से प्राप्त कर पा रह हैं।

इसी तरह बंगाणा निवासी मेद राम का कहना है कि उनके दो बेटे हैं दोनो ही व्यवसाय के चलते घर से दूर रहते हैं, ऐसे में उन्हें घर तक सामान पहुंचाने के लिए कुली करना पड़ता था लेकिन अब मिशन से यह काम आसान हो गया हैं।

पच्छाद में लोगों को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, सिरमौर

मिशन रीव के तहत सिरमौर के पच्छाद ब्लॉक के सराहा पंचायत में लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए शिविर का आयोजन किया। इसमें गोपाल सिंह, मोहनदास, कृपाराम, सहीराम, जितेंद्र, विजय सिंह, कमल राज, दीपक,रंजन सिंह, मोहि राम आदि किसानों ने भाग लिया इन सभी किसानों को मिशन रीव के सदस्यों ने जैविक खाद और जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ में मिशन रीव सदस्यों ने मिशन रीव द्वारा दी जा रही सभी सर्विसेस के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान लोगों ने मिशन रीव को लेकर कई सवाल भी पूछे।

विजय सिंह ने पूछा कि मिशन रीव के तहत किस तरह की सेवाएं दी जा रही है। इसके बाद सभी लोगों को मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि मिशन रीव के सदस्यों को सभी सर्विस कम दाम पर या निशुल्क दी जाती है। इसके साथ ही गांव के किसानों को विस्तार पूर्वक जैविक खाद बनाने के तरीके के बारे में भी बताया। इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी किसानों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया। रंजन सिंह ने कहा की जैविक खाद तैयार होने के बाद इसको कहां बेच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दी गई।

समस्याओं का समाधान कराने रीव के पास पहुंच रहे लोग

किसी को खेती तो किसी को चाहिए खेल का सामान

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत पंचायत फेसिलिटेटर गांवों में जाकर लोगों को अपनी तरफ से सेवाएं देने के साथ ही उनकी समस्याओं को जानकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके लिए गावों में लोगों के बीच जाकर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दंगील पंचायत के कड़ोग गांव में विशेष तौर पर युवाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान राजेश कश्यप, रितेश, गौरव, महेंद्र, गौरव और अन्य युवाओं ने बताया कि दिन भर खेतों में काम करके थकान मिटाने के लिए शाम को खेलना पसंद करते हैं लेकिन पर्याप्त सामान और सुविधा न होने के कारण खेल नहीं पाते। इन युवाओं ने मिशन रीव के तहत खेल सामग्री लेने की इच्छा जाहिर की। इसी तरह कंडाघाट की हिन्नर पंचायत में भी लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की गई। इस दौरान राकेश मानसिंह, प्रियंका, सपना ने बताया कि इस पंचायत में कृषि ओर पशुधन क अलावा लोगों की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।

ऐसे में पंचायत में डेयरी खोलने का विकल्प है लेकिन इसके लिए न तो लोगों को प्रक्रिया की जानकारी है न ही साधनों की उपलब्धता है। ऐसे में इन लोगों को मिशन रीव के तहत उन योजनओं और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है जिनसे स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सके।

पशुओं के स्वास्थ्य के साथ दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी

कैटल फीड सप्लीमैंट के सकारात्मक परिणामों से पशुपालक खुश

टीम रीव , ऊना

मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पशुधन को बढ़ावा देकर पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में मिशन रीव के तहत पंचायतों में पशुपालकों को कैटल फीड सप्लीमेंट उपलब्ध कराई जा रही है।

इस उत्पाद के बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कैटल फीड खिलाने वाले कुछ पशुपालकों से मिशन रीव की ओर से बात की गई तो पशुपालकों ने बताया कि कैटल फीड सप्लीमेंट से दुधारू पशुओं में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।कैटल फीड खिलाने के चार दिन के बाद ही जहां दूध की मात्रा में सुधार हुआ हैं वहीं पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

विनोद कुमार ने बताया कि वह काफी लम्बें समय से गौ–पालन कर रहें हैं, कुछ समय पहले ही उन्होंनें मिशन रीव की सदस्यता ली ।इस दौरान मिशन रीव के प्रतिनिधि ने उन्हें विभिन्न सेवाओं के साथ–साथ पशुओं के लिए कैटल फीड सप्लीमेंट की जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने मिशन प्रतिनिधी से ही फीड सप्लीमेंट प्राप्त किया और अपनी दुधारू गाय को देना शुरू किया।

विनोद ने बताया कि फीड देने के चार–पांच दिन के अन्दर ही गाय के दूध की मात्रा और गुणवत्ता के साथ ही उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। उन्होंने कहा कि मिशन रीव से उन्हें काफी लाभ हुआ है।

मेहर सिंह गाँव डोह अपनी भैंस के साथ

केस स्टडी

ऊना के विकास खण्ड बंगाणा के तहत बल्ह पंचायत के मिशन रीव में कार्य कर रहे सुखदेव पीएफ ने पंचायत में पहले मिशन रीव के बारे में लोगों को जागरूक किया और रीव के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे विभिन्न उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद गांव के लोगों को कैटल फीड सप्लीमेंट दी गई।

गाँव डोह के मेहर सिंह इसी फीड को नियमनुसार अपनी दूध देने बाली भैंस को दिया चार–पांच दिन खिलाया। इसके बाद उन्होने मिशन रीव को बताया कि कुछ ही दिनों के भीतर दूध में फैट और मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई हुई है। मेहर चंद ने मिशन रीव की सहराना की और कहा कि मिशन रीव बेहतरीन प्रयास है क्योंकि इसमें लोगों को घर पर ही सुविधाएं मिल रही है।

हैल्थ कैंप से सैकड़ो को हो रहा स्वास्थ्य लाभ

टीम रीव, सोलन

मोबाइल हैल्थ सर्विसेज के तहत मिशन रीव की ओर से विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मिशन रीव के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों को भी उनकी पंचायत में ही स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है।

जिला सोलन में मिशन रीव के तहत अभी तक करीब 20 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा चुका गांव में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से ग्रामिणों में भी खुशी की लहर है। सोलन ब्लॉक के के बाशिंदों कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे टेस्ट तक के लिए शहर जाना पड़ता था। अस्पतालों में टेस्ट कराने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंजतार करना पड़ता है।

अब गांव में ही विभिन्न तरह के टेस्ट की सुविधा है। इसके चलते स्वास्थ्य का ध्यान और समय–समय पर ब्लड टेस्ट कराने में आसानी हो गई है।

ककीरा पंचायत की ही तर्ज पर अन्य पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। लोगों की ओर से मिशन रीव की जमकर सराहना की जा रही है

योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा रीव

कृषि और स्वास्थ्य के साथ अन्य सेवाएं लेना भी हुआ आसान

टीम रीव, सिरमौर

सरकार की ओर से जनकल्याण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जनसमाज कल्याण की राह में रोड़ा बन रही इस समस्या का निवारण करने में आईआईआरडी का मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है।

रीव घर तक पहुंचा रहा जरूरत का सामान

प्रदेश के विभिन्न जिलों में रीव सरकार और आम जनता के बीच एक एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। जिला ऊना में मिशन रीव के तहत ऐसे कई उदाहरण है।

सिरमौर के पावंटा साहेब निवासी राजेंद्र राणा वह मिशन रीव के सदस्य के तौर पर वह 15 से अधिक सेवाएं ले चुके हैं। राणा का कहना है कि रीव गांवों के विकास को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केस स्टडी

नाम खेम राज जिला सिरमौर

सिरमौर जिले के खेमराज का कहना है कि कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है और वही उनकी आय का मुख्य स्त्रोत भी है। अभी तक वह अपने खेतों में अधिकतर रासायनिक खाद का ही प्रयोग कर रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होने मिशन रीव के तहत गांव में दिए जा रहे निशुल्क जैविक खाद प्रशिक्षण शिविर मे हिस्सा लिया और जैविक खाद बनानी शुरू की। अब जैविक खाद के बेहतरीन परिणाम सामने आ रहे हैं।

घर पर ही बन रहे लोगों के स्वास्थ्य कार्ड

सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहा मिशन रीव

ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते मिशन रीव के सदस्य

टीम रीव, कांगड़ा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने स्तर पर सेवाएं देने के साथ ही सरकारी योजनओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव बेहतरीन कार्य कर रहा है। अपने इसी प्रयास के तहत कांगड़ा जिला में मिशन रीव के तहत ढाई सौ से अधिक हैल्थ कार्ड बनवाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

गांव में ही इस सुविधा के मिलने के बाद लोगों ने भी मिशन रीव की काफी सराहना की। लंबागांब ब्लॉक के जोडबर गांव की रक्षा देवी ने का कहना है कि पहले हैल्थकार्ड बनाने के लिए धर्मशाला जाना पड़ता था लेकिन अब मिशन रीव के तहत घर पर ही हैल्थ कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की गई जिससे

घर पर ही मिल रही स्वास्थ्य कार्ड बनाने की सुविधा

काफी सुविधा हुई है। इसी तरह पंचरूखी ब्लॉक के छेब गांव की निर्मला देवी ने बताया कि पहले एक हैल्थ कार्ड बनवाने के लिए कंप्यूटर सेंटर के 10 चक्कर काटने पड़ते थे या कार्ड बनवाने के लिए पूरे परिवार को लेकर धर्मशाला जाना पड़ता था। लेकिन अब मिशन रीव के तहत घर पर ही यह सुविधा मिल रही है।

स्वास्थ्य कार्ड इसलिए जरूरी

बीते वर्ष ही यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम में उन लोगों को कवर किया जा रहा है, जो न तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आते हैं और न ही मुख्यमंत्री स्टेट हैल्थ केयर स्कीम में। ऐसे लोगों के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। इसमें एक दिन के एक रुपए (साल के 365 रुपए) में मरीज को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हैल्थ कार्ड बनाना जरूरी है। यह कार्ड एक साल, दो साल और तीन साल के लिए बनता है। हालांकि एक साल से ज्यादा अवधि के लिए कार्ड बनाने पर कुछ रियायत भी दी जा रही है। इससे उस वर्ग के तबके को काफी बड़ी राहत है जो सरकार की किसी भी स्वास्थ्य योजना में नहीं आते हैं। योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कार्ड बनाते समय में मरीज की पहले की स्थिति भी कवर की जाती है। यह सुविधा बहुत सी हैल्थ पालिसी में नहीं होती है। स्वास्थ्य योजना में सामान्य परिस्थितियों और क्रिटिकल केयर में यात्रा का खर्च देने का भी प्रावधान है।

ये हैं फायदे

- 30 हजार रुपए तक का कैशलैस इलाज
- गंभीर बीमारी पर 1.75 लाख तक की ट्रीटमेंट
- कैंसर पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर पर 2.25 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा

मिशन रीव से आसान हुई जीवन की राह

अब गांव में ही पहुंचा बाजार

टीम रीव, घुमारवीं

मिशन रीव के तहत लोगों को गांवों में ही उनके घर पर वह सामान पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए पहले उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करके बाजार जाना पड़ता था। लेकिन अब गांव में उनके अपने घर में ही मिशन रीव के तहत जरूरत का सारा सामान पहुंचाया जा रहा है। घुमारवीं ब्लॉक के ब्लॉक कोआर्डीनेटर परमिंदर संधु ने बताया कि पहले लोगों की जरूरतों को जानने के लिए कई शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई और उनको मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। दाबला पंचायत समेत अन्य पंचायतों में इस तरह के शिविरों का आयोजन करीब एक सप्ताह तक किया गया। इसके बाद लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया गया। इसमें कॉकरी, डिटर्जेंट, शैंपू समेत अन्य सामान लोगों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराया गया।

स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कॉकरी व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा

लोगों की जरूरतों को पहचान कर मिशन प्रतिनिधि कर रहे सहयोग

है। मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है। स्थानीय निवासी कमलेश, रीना , राकेश के मुताबिक मिशन रीव के जरिए वह रोजमर्रा की जरूरत का सामान आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं।

इसके साथ ही पशुओं के लिए कैटल फीड सप्लीमैंट भी उपलब्ध कराई गई। जिसके बेहतरीन परिणाम सामने आ रहे हैं।

मिशन रीव ने खोले रोजगार के द्वार

अपनी ही पंचायत में काम करने का मिला मौका

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाऐं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिषन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है।

ज़िले के अभी तक करीब सैकड़ों ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड

ऑनलाइन सिस्टम भी जान रहे ग्रामीण

पंचायत में ही रोजगार से खशी

स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया । इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में फेसिलिटेटर पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिपफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है ।

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है । लोगों को उनके घरों में ही टेस्ट सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से मिलने से ग्रामीण कापफी ख़ुश है।

दुधारू पशुओं के लिए वरदान साबित हो रही

कैटल फीड सप्लीमेंट

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर जिले की बड़सर तहसील में दुधार गांव के विजय कुमार ने मिशन रीव के तहत पशुओं के लिए तैयार किए गए फीड सप्लीमेंट का उपयोग किया और उसके बाद गाय के दूध और गुणवत्ता में परिवर्तन देखने को मिला। कैटल फीड को 3 दिन तक अपनी दुधारु गाय को खिलाने के बाद दूध की मात्रा के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता में भी अंतर पड़ गया । पहले गाय एक समय में 3 किलो दूध देती थी जबकि कैटल फीड खिलाने के बाद दूध की मात्रा बढ़ना आरम्भ हुई । दस दिनों के बाद 3 किलो दूध की मात्रा बढ़ कर साढे चार किलो एक समय में हो गई तथा गाय के दूध पर लगने वाली मलाई की मात्रा भी बढ़ गई । मलाई पहले से अधिक मोटी परत के साथ दूध पर आना शुरु हो गई । इतना ही नहीं दूध से घी बनाने पर घी की गुणवत्ता एवं मात्रा में भी इजाफा हो गया । विजय कुमार ने बताया कि फीड को नियमित रूप से दिशा निर्देशों के साथ दुधारु पशुओं को दिया जा रहा है तथा इस फीड के गुणों को देखते हुए इसकी मांग गांव भर में बढ़ गई हैं।

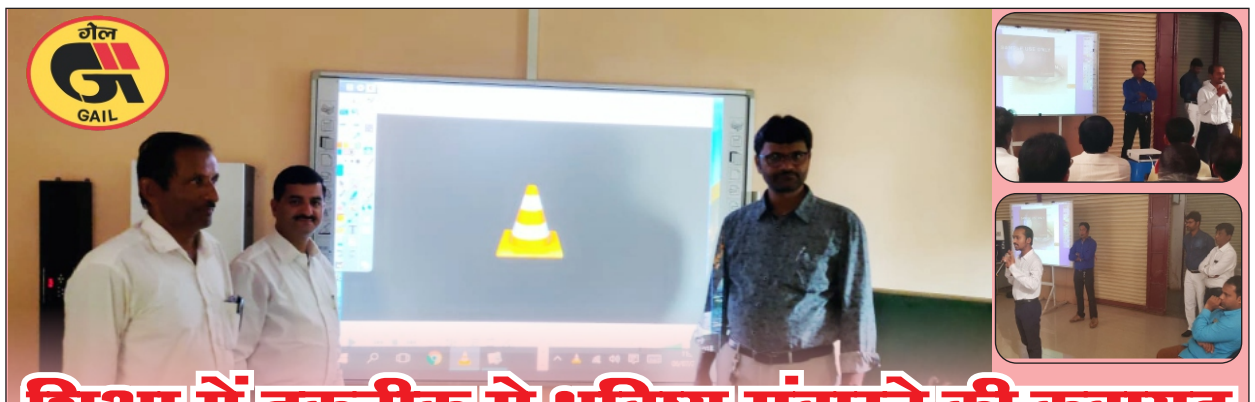

शिक्षा में तकनीक से भविष्य संवारने की कवायद

आईआईआरडी ने कर्नाटका में शुरू किए स्मार्ट क्लासरूम

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल करते हुए गेल इंडिया के साथ मिलकर आईआईआरडी ने कनार्टका के हुबली में 40 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। इसमें कन्नड़ भाषा में सभी विषयों को डिजीटाइज किया गया।इसके साथ ही इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस प्रयास से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ अध्यापकों की अध्यापन क्षमता में भी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। अभी 40 और विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है।

Thanks GAIL India Ltd. for recognizing our competency in CSR domain

कुल्लू में स्वास्थ्य स्लेट से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल

घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने से ग्रामीणों को राहत

टीम रीव, कुल्लू

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके चलते गांव में लोगों को काफी राहत है क्योंकि लोगों को बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। कुल्लू की 60 वर्षीय मीना देवी के परिवार वालों के मुताबिक मीना को अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है क्योकि अस्पताल उनके घर से काफी दूर है और वह अस्पताल जाने को तैयार भी नहीं होती लेकिन स्वास्थ्य स्लेट से घर पर ही उनके टेस्ट हो जाते हैं। इसे उन्होंने काफी राहत महसूस की है।

स्वास्थ्य स्लेट के लाभ

स्वास्थ्य स्लेट से वह सभी टेस्ट किए जाते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को होने वाले रोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। स्वास्थ्य स्लेट से एचबी, बीपी और शुगर समेत अन्य टेस्ट किए जाने की सुविधा है।

हेमोग्लोबिन टेस्ट

इस टेस्ट से खून मे हेमोग्लोबिन नामक तत्व की प्रतिशतता की जांच की जाती है। खून मे हेमोग्लोबिन की कमी को अनीमिया कहा जाता है। इससे शारीरिक थकावट, सांस लेने मे दिक्कत, भूख न लगना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शुगर टेस्ट मधुमेह

(सामान्य शुगर 80–120)

शुगर टेस्ट से मधुमेह नामक रोग की जांच होती है इस टेस्ट से रक्त मे ग्लूकोज़ तत्व के कम या अधिक मात्रा मे होने की जांच की जाती है।

शुगर अधिक हाने पर व्यक्ति मधूमेह का शिकार हो जाता है। वजन घटना, बार–बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, प्यास लगना, जख्म भरने में देरी होना, हड्डियों का कमजोर होना, किडनी फेल होने की समस्या बढ़ जाना समेत अन्य कई तरह की स्वास्थ्य संबंधि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर शुगर का टेस्ट करना जरूरी है और इसमें स्वास्थ्य स्लेट बेहद कारगर साबित हो रही है।

रक्तचाप बीपी

रक्तचाप अधिक होने से हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और दूसरी गंभीर समस्याएं हो सकती है।

पल्स आक्सीमीटर

इस टेस्ट से खून में आक्सीजन की सही मात्रा का पता लगाया जा सकता है। आक्सीजन की मात्रा सही न होने से सांस संबंधि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समय समय पर टेस्ट कराना जरूरी है।

टाइफाइड टेस्ट

यह रोग दूषित खाद्य पदार्थों और गन्दे पानी के सेवन से होती है। इसमें व्यक्ति को बुखार आ जाता है। समय पर टेस्ट न होने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।

निरमंड और आनी में आसान हुई जैविक खेती की राह

निज़ुल्क प्रज़िक्षण से सैंकड़ों किसानों को लाभ

टीम रीव, कुल्लू

मिशन रीव के तहत सोलन की विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर से उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर भी दिया जा रहा है। अन्य जिलों के साथ–साथ जिला कुल्लू में भी लोगों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल्लू में दो सौ से अधिक किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं।

आनी और निरमंड में लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। स्थानीय लोगों भीम सिंह, ध्यान सिंह, नैन सिंह व अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक जैविक खाद के बारे में कई बार सूना था लेकिन यह कैसे बनती है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों

200 से अधिक किसानों को दिया जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण

को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर कुछ पूछना हो तो आईआईआरडी के पंचायत फेसिलिटेटर अपनी ही पंचायत में उपलब्ध हैं जो तुरंत सेवा प्रदान करने को तैयार रहते हैं।

मिशन रीव से आसान हुआ दूरदराज के गांवों में जीवन

चंबा में घर-घर मिल रही सेवा

टीम रीव, चंबा

चंबा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही।

लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत न केवल लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

हाल ही में ग्राम पंचायत उदयपुर में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया और लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एनीमल फूड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान उनके घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया।

इस दौरान लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे साबुन, क्रॉकरी, शैंपू आदि भी लोगों को घरों तक पहुचांया जा रहा है।

ऑर्गेनिक खाद के बाद अब मृदा परीक्षण की सुविधा देगा मिशन रीव

आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

टीम रीव, कांगड़ा/हमीरपुर

प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए ऑर्गेनिक खाद के बाद एक और अच्छी खबर है। आईआईआरडी मिशन रीव के तहत जल्द ही गांवो में मृदा परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईआरडी शिमला में दिया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने की योजना है। लैब में मृदा परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित की जाएंगी जिसमें किसानों को स्टीक और समयबद्ध रिपोर्ट मिल सकेगी। इसी के तहत अन्य जिलों के साथ साथ कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर में भी मशीने स्थापित की जाएंगी जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मृदा परीक्षण क्यों?

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधे खडा रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।

मुख्य तत्व

कार्बन, हाइडोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम।

सूक्ष्म तत्व

जस्ता, मैग्नीज, ताँबा, लौह, बोरोन, मोलिबडेनम व क्लोरीन।

इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है।

यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाए जो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बड रहा है। परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है।

मृदा परीक्षण के उद्देश्य

मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।

मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अमलीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करना।

फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

किसी गांव, विकास खंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदा की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना। इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना।

प्रयोगशाला में मृदा की जांच

मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है की मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। यदि मृदा का नमूना ठीक डंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परीक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों न बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। खेत की मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए

मंडी में जैनरिक स्टोर से मरीजों को सुविधा

सस्ती दवाओं से इलाज करना आसान

टीम रीव, मंडी

मंडी के दो स्थानों पर हाल ही में दो जनऔषधि केंद्रों का लोकापर्ण किया गया है। आईआईआरडी की ओर से छतरी और बंगरोटू में खोले गए इन जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सस्ती दवाईयां आसानी से पहुंच रही है। इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए दूर शहरों में भटकना पड़ता था।

आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में तीन सौ जनऔषधि चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

इसी के तहत मंडी में भी केंद्र खोले गए हैं और यहां पर लोगों को असानी से सस्ती दवाईयां उपलब्ध हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है इन केंद्रों के खुलने से इलाज पर होने वाला खर्च लगभग आधा हो गया है तथा इस तरह के केंद्र सभी स्थानों पर खुलने चाहिए जिससे लोगों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाईयां आसानी से मिल सके।

प्रदेश को मिले पांच जन औषधि केंद्र

टीम रीव, शिमला

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता एवं नियमित चैक अप व स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पांच जनऔषधि केन्द्रों का विधिवत लोकार्पण अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश बीके अग्रवाल ने किया। इस मौके पर रीव सचिवालय शनान, शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यातिथि ने जैविक खेती और जैविक खाद के आउटलैट्स, मोबाइल लैब आदि का निरीक्षण भी किया और आईआईआरडी द्वारा चलाई जा रही जन सेवाओं को सराहा एसीएस ने सबसे पहले आईआईआरडी कार्यलाय शनान में जनऔषधि कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद इसी कार्यालय से ही मंडी के छतरी, बंगरोटू, कांगड़ा के नूरपूर और पालमपुर, हमीरपुर के जाहु में आईआईआरडी द्वारा खोले गए जनाऔषधि केन्द्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसीएस बीके अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और लोगों को दवाईयों के लिए अब नहीं तड़पना पड़ेगा तथा जनऔषधि केन्द्रों से अब सभी को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता होगी।

ये होगी सुविधा

आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध होगी। इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए शहरों में भटकना पड़ता था।

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में तीन सौ जनऔषधि केंद्र चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

इस मौके पर आईआईआरडी की निदेशक सुषमा शर्मा, सह–निदेशक एसके शर्मा, फ्लायर ग्रुप के निदेशक और सीईओ आनंद नायर, एचओडी रीव क्लीनिक मोबाइल पैथ लैब डा. केआर शांडिल, मिशन हैड एनके शर्मा, सीनियर ऑपरेटिंग ऑफिसर गौरव द्विवेदी, राज्य समन्वयक सुरेंद्र कुमार व स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

पेज 1 का शेष

मिशन रीव में क्या नया ?

गौरतलब है कि इस प्रकार की यह अपने आप में अद्वितीय पहल है । मिशन रीव चला रही संस्था आईआईआरडी का दावा है कि इस तरह की पहल अभी तक विश्व के दूसरे देशों में शरू नहीं हुई है। हालांकि टेलीमेडिसन के कुछ प्रारुप देश में चल रहे हैं लेकिन उसका दायरा काफी सीमित है। जबकि मिशन रीव की टेलीमेडिसन सेवा इस दृष्टि से काफी व्यापक है।

रीव टेलीमेडिसन सेवा के तहत एक व्यक्ति को उसके घर पर ही जांच से लेकर जरूरी उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके साथ ही समय–समय पर डाक्टरी परामर्श और दवाईयों की उपलब्धता भी मरीज के घर पर ही मिशन प्रतिनिधियों के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। रीव टेलीमेडीसन की यही विशेषता इसे दूसरी स्वास्थ्य प्रणालियों से अलग करती है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पाई हैं। सरकार अपने स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ समय–समय पर लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करती है लेकिन धरातल पर ऐसी सभी योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाती।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य कार्ड की योजना को बहुत हद तक आम लोगों विशेष तौर पर ग़रीब तबके को राहत की गारंटी के साथ सामने आई है । लेकिन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी भी जन–जन तक पहुंचनी बाकि है।

आम तौर पर लोग आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं है और जाने –अनजाने बीमारी का शिकार हो जाते है। अक्सर यह देखा गया है कि अधिकतर लोग तभी अस्पताल जाते है जब वह बीमारी की चपेट में आ जाते है। लेकिन तबतक काफी देर हो जाती है और ईलाज मंहगा हो जाता है और कई बार यह मंहगा ईलाज जेब और

जान दोनो पर भारी पड़ जाता है।

इन्हीं परिस्थितियों की वास्तविकता और गहन अध्ययन के बाद मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्यक्रमों एवं प्रभावशाली योजनाओं के साथ लोगों को उनका कीमती समय और धन को बचाते हुए दूरगामी क़दम उठाते हुए रीव टेलिमेडिसन को जेनेरिक औषधि से जोड़ा है।

जेनेरिक औषधि केन्द्रों के खुलने से हिमाचल भर में लोग गांव में ही सस्ती और भरोसेमंद दवाईयों की उपलब्धता ले सकेगें । अभी पांच जनऔषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं और शीघ्र ही हर ज़िले में इन केन्द्रों को आवश्यकता आधारित खोलने की प्रक्रिया जारी है । टेलिमेडिसन इस प्रक्रिया के अंतर्गत संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा की ओर बेहतरीन पहल है ।

कैसे काम करती है प्रक्रिया

क्या इस प्रकार का ये प्रयास अनूठा नहीं कहा जाएगा ? व्यक्ति को न आने–जाने का झंझट, न जांच एवं उपचार की चिंता.....घर से ही स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच से घर पर ही संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार की यह पद्धति विश्व की अनुपम एवं रीव की सतत शोध का परिणाम है ।

रीव टेलिमेडिसन प्रक्रिया मे स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है क्योंकि सभी कुछ पारदर्शी एवं बहुत ही साधारण तरीके से शीघ्रता से कर लिया जाता है ।

दूसरी ओर अभी जनाऔषधि केन्द्रों की भारी कमी के चलते सस्ती दवाईयों की उपलब्धता नोटबंदी में नोटों की कमी जैसा ही लग रहा हैं । आसानी से दवाईयों का मिलना संभव नहीं हैं । सबसे बड़ी क़िल्लत दवाईयों की हैं जो कि वर्तमान में सीमित मात्रा में ही जनाऔषधि केन्द्रों पर उपलब्ध हैं । आख़िर में खुले बाज़ार में मंहगी दवाईयों से ही गुजारा करना पड़ता हैं । सरकार की भूमिका सेवाओं की उपलब्धता एवं प्रशासन पर इसे समुचित प्रकार से लागु करने की होती हैं जिसे कम से कम अभी तो दुरुस्त करने की ज़रुरत हैं ही ।

ऐसे में मिशन रीव जनऔषधि केन्द्रों और उनमें लगभग सभी प्रकार की दवाईयों की उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए सार्थक पहल कर रहा हैं ।

इन जनऔषधि केन्द्रों को रीव टेलिमेडीसन सेवा के साथ जोड़कर लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।

India spends just USD 63 per capita per year on health: WHO report

India's per capita expenditure on health spends at a dismal US$ 63, less than that in neighbouring Bhutan and Sri Lanka, says recently released report "World Health Statistics report" by the WHO. The life expectancy in India is just 59.3 years which is very low as compared to several other developing countries.

India's per capita health expenditure per is among the lowest for developing countries with China reporting a per capita spending of US$ 426, Thailand US$ 217, Malaysia US$ 386, Philippines US$ 127, Sri Lanka US$ 118 and Indonesia US$ 112. Among the SAARC countries, Pakistan has a per person health expenditure lower than India's at US$ 38 while Bhutan has a better spending of US$ 91.

The report also says that India's health spending is a measly 3.9% of GDP. Of this, public spending is just 1.15%, which the government aims to raise to 2.5% by 2025. In comparison, developed countries have much better health expenditure figures with the USA reporting US$ 9,536, UK US$ 4,356 and Germany spending US$ 4,592 per capita per year.

In its new health policy released in March last year, the Centre had said it that it will allocate two-thirds of its budgetary resources to primary health,

The life expectancy in India is just 59.3 years which is very low as compared to several other developing countries.

convert primary health centres into "wellness centres" with a focus on prevention and health promotion, and deploy more doctors and paramedics in public hospitals facing shortages. The policy had also set several quantitative goals, including increasing India's life expectancy at birth from to 70 years by 2025 and reducing premature mortality from cancer, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases and diabetes by 25 per cent by 2025.

सेहत तय करेगी प्रौद्योगिकी की संभावना

यह निर्धारित करने में आपका स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि आप उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) और जीन एडिटिंग के अनुकूल हैं या नहीं। एक विशेषज्ञ ने इस पर जोर दिया है। वैश्विक शोध कंपनी फोरेस्टर के प्रमुख विश्लेषक और उपाध्यक्ष जेम्स एल. मैक्वीवे ने कहा, 'एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में नई फायदेमंद प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना अधिक होगी।

यह भविष्य की प्रौद्योगिकी को अपनाने के दौरान काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगे कहा, 'भविष्य में जो नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, उससे स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा फायदा मिलेगा।' उनके मुताबिक, शारीरिक स्वास्थ्य भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जो बौद्धिक चपलता, नवाचार के लिए खुलापन और अंततः प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञ ने कहा, 'इसका उत्पाद प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन यह सामाजिक भी है, क्योंकि कई आगामी नवाचारों में स्वास्थ्य और कल्याण भी शामिल होगा।

यह स्वास्थ्य को नई डिजीटल खाई का कारण बना देगा। जिनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, वे उनका प्रयोग कर पाएंगे, और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वे इसे अपनाना नहीं चाहेंगे।'हालांकि केवल बेहतर स्वास्थ्य ही इस बात का सूचक नहीं है कि वह व्यक्ति प्रौद्योगिकी और नवाचार को पसंद करता हो और उसे अपनाना चाहता हो। इसमें समाज और व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रमुख भूमिका होती है, जो स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकती है। हालांकि आखिरकार इनमें धन की प्रमुख भूमिका होती है। क्योंकि आपको टेस्ला की कार खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे, चाहे वह ए.आई. हो या जीन एडिटिंग हो।' उनका कहना है कि भविष्य के प्रबंधक केवल अधिक स्वस्थ लोगों को ही काम पर रखना पसंद करेंगे तथा भविष्य के विक्रेता भी अधिक स्वस्थ ग्राहक चाहेंगे।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का दूसरा अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पहला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा।

द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर
प्रबन्ध संपादक

द रीव टाइम्स
संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स
पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक
श्री प्रदीप कुमार जेरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस
सायबू निवास समीप सेक्टर -2 ,
बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9,
हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा,
प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761,
मेलः editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

उत्तरदायित्व का अकाल

कुछ दिनों पूर्व दिल्ली से शिमला की ओर आने वाली एक सरकारी बस रात को चण्डीगढ़ पार करते हुए एक स्पीड ब्रेकर से ज़ोर से टकराई । शायद उस जगह पर बना स्पीड ब्रेकर नया था और ड्राईवर को उसका पूर्वानुमान न था । गाड़ी ज़ोर से उछली और सभी यात्री अपनी सीटों से इधर–उधर गिर पड़े । एक अधेड़ उम्र व्यक्ति जो अंत की मध्य वाली सीट पर बैठा था, वह बीच बस में जोर से गिरा तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द के कारण जोर से चिल्लाने लगा। सवारियों की मध्यस्तता से ड्राईवर ने तुरंत बस को पीजीआई चण्डीगढ़ की ओर मोड़ा। कुछ सवारियों ने मरीज को आराम से बस से उतारा और आपातकाल सेवा यानि इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया। एक्स–रे, सीटी स्कैन आदि सब होते–होते चार घंटे का समय बीत गया । आख़िर मरीज की रीढ़ की हड्डी में हल्की दरार बताई गई। इसी बीच संबंधित विभाग के दो अधिकारी भी अपनी प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज़ कराने अस्पताल पहुंचे । सवारियों ने पूरा सहयोग करने के बाद कथित अधिकारियों से आग्रह किया कि मरीज का ख़्याल रखें व अस्पताल के खर्चे में मरीज की सहायता करें। बस सुबह के करीब सात बजे शिमला रवाना हुई ।

डॉक्टर के परामर्श के अनुसार10 दिनों के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी हो गई और अब कम से कम छः महीनों के लिए वह बिस्तर पर है। इलाज़ के खर्चे की संबंधित विभाग से उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई । कई बार संबंधित निकाय तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल भेजी गई पर कहीं से कोई जवाब न मिला। इस बीच प्राइवेट नौकरी भी चली गई। पत्नी एक निजी विद्यालय में पढ़ाती थी, अब नौकरी छोड़ पति की सेवा में लगी हैं। परिवार की आर्थिकी ज़मीन पर आन पड़ी । इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, यह विषय सतत चिंता का कारण हैं ।

अंततः मरीज को बस वालों पर मुकद्मा बनाना पड़ा और अब अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ–साथ वर्षों न्यायायिक प्रक्रिया में अपना समय झोंकेगें। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक कारोबारी व्यक्ति जब अचानक इस प्रकार के हादसे का शिकार होता हैं तो जीवनयापन के सारे विकल्प प्रभावित होते हैं। इससे भी अधिक एक आत्मग्लानि कि काश उस बस में न जाता, तो ऐसा न होता !

उस व्यक्ति की क्या यही ग़लती थी कि वह उस बस विशेष में यात्रा कर रहा था ? उसके आगे के जीवन व परिवार के पालन–पोषण के बारे में कौन सोचेगा ? क्या हमारे सरकारी महक़मों या निकायों से कम से कम अस्पताल के बिल देकर अपना प्रारंभिक दायित्व भी पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती हैं ? आख़िर क्यों हम बिना न्यायालय के आदेशों के ही समुचित कदम नहीं उठाते ? क्या यह हमारी मस्तिष्क की निष्क्रियता है या जनमानस के प्रति उदासीन रवैया ? जबकि दूसरी ओर सहयात्रियों ने संवेदना का परिचय दिया, मरीज़ को उठाया, लेटाया, उपचार का सामान खरीदा, बिस्तर की सफाई की और पूरे चार घंटे अस्पताल में मरीज के साथ खड़े रहे। मरीज के साथियों ने अटैंडेंट की वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही बस को चण्डीगढ़ से शिमला रवाना किया। यह घटना शासकीय व्यवस्था में जमें अधिकारियों और आम जनता की सोच में व्यापक खाई की ओर इंगित करती हैं। क्यों न अधिकारी विशेष की जिम्मेवारी निश्चित की जाए इस प्रकार के विषयों पर कदम उठाने से हुई क्षति की व्यक्तिगत स्रोत से आपूर्ति के लिए ?

देश की जनता ने जब लोकतंत्र की नींव रखी थी, शायद यह नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही शासन व्यवस्था आगे चल कर उनसे सौतेला व्यवहार करेगी। ग़ौर से सोचेंगें तो शासकीय उत्तरदायित्व के रोजमर्रा के जीवन में अनगिनत ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिनके उत्तर मिले बिना जनता निरुत्तर हो जाती हैं ।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक

Social Sector - Learning Opportunities for Young Professionals

Social sector is an important sector for India's economy and includes several important components such as education, health and medical care, water supply and sanitation, poverty alleviation, housing conditions etc. that play a vital contribution in human development.

This sector also provides learning opportunities and experience across a range of organisational functions. No wonder, there is a growing trend among young professionals to add such experience to their CV. Even MBA aspirants have jumped on to the bandwagon. Is this trend restricted to India only, the answer is a big NO! Increasingly, professionals and students worldwide are seeking out opportunities in the development sector in emerging economies, to work on some of the most pressing problems of the world, broaden their horizons and be ahead of their peers in terms of exposure and experience. For example, 27-year-old American (name withheld on request) is a Lok Capital Fellow with a Microfinance company in Navi Mumbai. For your information, Lok Capital is an investor in the social sector, and the microfinance institution he is working for lends to women in India. This is just one example, there are many such professionals who are working in social sector, forgoing the luxury and perks that can be theirs in the corporate world.

Why are they doing so? The most pertinent answer to this is that these opportunities provide insights and a detailed understanding of the customers of social enterprises that one would not get as an investor, and that, this experience would be invaluable as one transitions to an investing role. The job in social sector give them the opportunity to gain experience that would have been nearly impossible in a big corporation. While the experience and training gained at a large corporation are tremendous, they would never get the freedom to take the lead on the number of projects at one time while working in the social sector. Also, corporate life is all about numbers. Sometimes one loses sight of why we do what we do. Working in the social sector reminds us of the important things by showing the interconnectedness of life.

Job aspirants are increasingly seeking out corporate-backed not-for-profit organisations for such experience. And, what are they seeking out of social sector job.... most of them want to make a difference. It's a known fact that professionals look at the social sector as a means to become better at their jobs. Working for a cause that improves someone's life makes one a better manager, a better parent and more importantly a better human being.

Mission RIEV has embarked upon providing universe of opportunities to 10,000 job aspirants in coming times and from various fields and educational background .

I would like to end with a quote of Mahatma Gandhi, *"The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others."* Mission RIEV gives you this opportunity.

Anand Nair
Managing Editor
anand@iirdshimla.org

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियां

''सच्चा भारत अपने कुछ शहरों में नहीं अपने छः लाख उन्चास हजार चार सौ इक्कासी गावों में पाया जाता है। यदि गावों का विनाश होता है तो भारतवर्ष का भी विनाश हो जाएगा''

मोहनदास कर्मचंद गाँधी

भारतीय समाज बहुल संस्कृतियों, और जातियों व जन–जातियों, तथा बहु–भाषी और शहरी एवम् ग्रामीण असमानताओं से भरपूर समाज है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतवर्ष ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बुनियादी ढाँचा, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है।

बावजूद इसके ग्रामीण भारत का अधिकांश हिस्सा आजादी के 70 वर्षों उपरांत भी सामाजिक मीडिया के लिए अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है। तकनीकि विकास के बावजूद आम आदमी के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास आज भी एक सरल एवम् सीधी– सादी नहीं बल्कि बहुआयामी जटिल प्रक्रिया बनी हुई है। मेरी समझ से इस के प्रमुख कारण इस प्रकार है :

- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों में तालमेल का अभाव
- सरकारी योजनाओं के प्रारूप का लाभार्थियों को ज्ञान न होना
- सरकार के पास किसी भी इकाई का सटीक आँकड़े न होना
- सरकारी काम पूरा हो जाने पर किसी की जवाबदेही का न होना
- काम पूरा हो जाने पर उसका सामाजिक ऑडिट लाभार्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा न होना
- किसी भी क्षेत्र के लिए दीर्घ कालीन योजनाओं का अभाव
- सरकारी अनुदान प्राप्ति में जटिल प्रक्रियाओं का होना
- कागजी कार्यवाही की जटिल प्रक्रिया का होना
- इन कारणों के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र विशिष्ट के अनेक कारण हो सकते हैं जिन के फलस्वरूप सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लक्षित लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है । यों तो भारत सरकार प्रांतीय सरकारों के साथ मिल कर बड़ी–बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में प्रयासरत है, लेकिन धरातल पर नतीजे सरकारी आँकड़ों से मेल नहीं खाते ।

शायद इस का मुख्य कारण उपलब्ध जनसूचना माध्यमों का सही इस्तेमाल का न कर पाना हो सकता है बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग इस बात का अहसास तो करवाते हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो रहा है, लेकिन वांछित लाभार्थी इन प्रचार माध्यमों से दूर कहीं अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने में तमाम दुनिया से अलग कहीं खोया हुआ है।

तमाम दावों के बावजूद अधिकतर गाँवो तक इन प्रचार माध्यमों की पकड़ न के बराबर है। अधिकांश मामलों में तो सरकारी योजनाओं का पता ग्रामीणों को कई सालों बाद चलता है और तमाम सरकारी प्रयासों के बाबजूद वे योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। फलस्वरूप , लाभार्थी इन सरकारी योजनाओं से अनभिग्य रह जाता है।

जमीनी सतह पर योजनाओं की असफलता का एक और कारण सरकार के पास सटीक आँकड़ों का न होना भी है। चूँकि जनगणना दस सालों में एक बार होती है अतः कभी–कभी योजनाएँ 10 वर्षों पुराने आँकड़ों के आधार पर बनाई जाती हैं।

इन हालातों में ज्यादातर लाभार्थी या तो पलायन कर चुके होते हैं या कोई कारोबार कर के लाभार्थी समूह से बाहर हो जाते हैं या असमाजिक तत्वों के चुंगल में आकर इन समूहों से बाहर हो जाते हैं ।

अधिकतर सरकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन उपरांत कोई भी जिम्मेवार नहीं होता। कई बार तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी सरकारें पूर्व सरकार द्वारा किए गये कार्यों को मान्यता तक नहीं दे पातीं। विभिन्न राजनीतिक दलों की कार्यसूची का अलग होना शायद इस का कारण हो सकता है। शिक्षित एवम् जागरूक समाज केवल इसी कारण से सरकारी योजनाओं पर भरोसा नहीं करता।

सरकारी परियोजनाओं का किसी सामाजिक संस्था या लाभार्थियों के समूह की द्वारा सामाजिक ऑडिट करवाया जाना भी एक अति सामाजिक संतुष्टि का महत्वपूर्ण कारण है। अतः ये जान लेना भी जरूरी है कि सरकार द्वारा लाई गई परियोजना समाज को कितना प्रभावित कर पाई।

अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारों के पास अधिक दीर्घ–कालीन योजनाएँ नहीं हैं, हालाँकि अल्प कालीन योजनाएँ धरातल पर कार्यरत हैं पर किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक दीर्घ कालीन योजनाओं का होना ही उस क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने में सहायक होता है। छोटे छोटे स्तर पर चलाई जाने वाली योजनाओं से किसी भी क्षेत्र के निवासियों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है ।

इसके इलावा सरकार द्वारा प्रायोजित परियोनाओं का लाभ उठाने के लिए इतनी अधिक कार्यवाही करनी पड़ती है कि ग्रामीण निवासी सरकारी एवं गैरसरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते–लगाते हताश हो कर उस में से अपना हाथ खींच लेते हैं। हालाँकि कई परियजनाओं में सरकारों ने एकल खिड़की प्रणाली का आगाज कर दिया है लेकिन यह केवल शहरों और कुछ कस्बों तक ही सीमित हो कर रह गया है।

उपरोक्त सभी कारणों पर सहयोगात्मक एवं सकारात्मक पहल करते हुए आईआईआरडी शिमला ने मिशन रीव का शुभारंभ प्रायोगिक परियोजना के रूप में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए लगभग 3500 पढ़े लिखे, प्रशिक्षित एवम् प्रगतिशील युवा हर प्रदेश वासी के द्वार पर सेवा देने के लिए तत्पर हैं। बात कृषि की हो, ग्रामिणों के स्वास्थ्य की हो या गांवों को ऑनलाईन सर्विस देने की हो, हम समस्त सरकारी जन–कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आम–जन तक सटीक एवं सार्थक रूप से पहुंचाने के प्रति कृतसंकल्प हैं । आईआईआरडी का मिशन रीव गांवों की तस्वीर को बदलने के लिए एक क्रांतिकारी मिशन साबित हो रहा हैं।

एस.के. शर्मा
sksharma@iird.org

Editorial Team

Anjna Thakur
Associate Editor

Hemraj Chauhan
Associate Editor

Narender Thakur
Composer & Graphics Designer

क्या से क्या हो गया.....हमारा शिमला

कभी शिमला का नाम सुनते ही खूबसूरत पहाड़ों पर स्वर्ग सा सुन्दर दृश्य और मनोरम छटा बिखेरता एक ऐसा सुंदर वातावरण ज़हन में आता था, जिसे याद कर हम कंही खो जाते हैं । लेकिन, आज वही शिमला अपनी बद्तर होती जा रही हालातों पर मूक हो गया है । अब शिमला की पहचान बदल गई है । शिमला का नाम सुनते ही पानी की क़िल्लत, कंकरीट का जंगल, सीवरेज से भरी सड़कें, अव्यवस्थित यातायात, बढ़ते पर्यटकों के कारण अव्यवस्था के चलते स्थानीय निवासियों को हो रही समस्याओं, बंदरों की बढ़ती आबादी से आमजन की असुरक्षा एवं परेशानी आदि ही जहन में आता है ।

भूस्खलनः आने वाली विपदा का संकेत

लगातार हो रहा निर्माण कार्य शिमला पर बोझ बन गया है

शिमला शहर की स्थापना अंग्रेजों ने बहुत सोच–समझकर दूरगामी दृष्टि से की थी । यही कारण था कि उनके तत्कालीन समय में शिमला अति कठोर व जटिल नियमों से भी बंधा था । मॉल रोड़, रिज़ पर घूमना या गंदगी तो दूर.....मॉल पर चलने और घूमने की भी नियमावली थी जो किसी पाबंदी से कम न थी । 1875 में 16,000 की आबादी को बसाने के लक्ष्य से शिमला का निर्माण हुआ था । वृक्ष और हरियाली यहां की आत्मा के मूल रहे हैं । परंतु बीस हज़ार का आंकड़ा आज 5 लाख के क़रीब हो चुका है । टिड्डी दल की तरह ईमारतें भी बनी और आबादी का बोझ भी इस पहाड़ी पर बढ़ता गया । ठीक वैसे ही जैसे 52 सीट्स वाली बस में 100 लोग चढ़ जाऐं तो बस की स्पीड और सुरक्षा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है परन्तु उसी बस पर 500 लोग चढ़ना चाहे तो बस की हालत क्या होगी..... यह अंदाजा लगाया जा सकता है । शिमला की पहाड़ी भी इसी प्रकार से बोझ तले दबती जा रही है । आबादी का बोझ, कंकरीट के मलबे का भार, कब तक ये पहाड़ अपनी गोदी में उठाएगा ? प्रलय पूछ कर नहीं आता..... लेकिन हम उसे बुला–बुला कर आंमत्रण दे रहे हैं । यहां के पानी की गुणवत्ता और वायु की शुद्धता जीवन के लिए अमृत्व से कम नहीं रही । लेकिन आज पानी के कारण ही गाहे–ब–गाहे लोग जान से हाथ धो रहे हैं । यातायात की तो बात ही क्या कहनी ? हवा में ज़हर घोलता प्रदूषण तो एक तरफ.....शिमला में एक किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा भी लग जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए ।

किसी भी राज्यों के लिए पर्यटकों का आगमन सुखद एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का परिचायक हैं । पर्यटन आर्थिकता के साथ–साथ वहां की खूबसूरती का ब्रांड भी होता है । किंतु शिमला के संदर्भ में यह अनमना एवं अटपटा सा लगने लगा है । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला एक विश्वस्तरीय स्थल है किंतु अब यहां स्थितियां बदल रही हैं । साधन–संसाधनों के अभाव में मूलभूत सुविधाओं का अकाल महसूस किया जा सकता है । बेतरतीब निर्माणाधीन व निर्मित कंकरीट के जंगल, जलापूर्ति की लचर एवं अव्यवस्थित व्यवस्था, यातायात की लंबी कतारों में दम घुटती ज़िंदगी और अनमोल समय का नाश, अव्यवस्थित कूड़ा–कचरा प्रबंन्धन आदि ने शिमला की तस्वीर बदल दी है । अब शिमला आकर्षण का केन्द्र नहीं, कोसने का माध्यम बनता जा रहा है ।

आए दिन शिमला नगर निगम की सफाई व्यवस्था कटघरे में खड़ी रहती है । कूड़े के ढेर और कूड़ा प्रबन्धन में लगभग असफल हो चुकी व्यवस्था इसकी खूबसूरती को दागदार कर रही हैं ।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीआईएस) ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि शिमला अत्यधिक भार तले दबता जा रहा हैं । अंधाधुंध निर्माण कार्य किया गया और हो भी रहा है जिससे शिमला धंसने के कगार पर है

कितना बोझ सहेंगी हिल क्वीन

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि रिवोली बस अड्डा और लक्कड़ बाज़ार में भूस्खलन हो रहा हैं जो कि ख़तरनाक हैं । ऐसा ही परिदृश्य प्रतिवर्ष तिब्बति मार्केट, स्कैंडल प्वांईट के नीचे देखने को मिलता है । रिज़ मैदान कितनी बार धंस कर अपने वास्तविक स्वरुप को खोता जा रहा है । साथ ही ख़तरा तो बना ही हुआ है ।

अभी हाल ही में एक स्वच्छता अभियान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मालूम पड़ा कि सच्चाई कितनी कड़वी होती है । खलीनी के जंगलों में कूड़े के ढेर, शिमला मॉल रोड़ के पास नालों में गंदगी और सीवरेज की पाईप लाईन हर क्षेत्र में टूटी–फूटी.....क्या यही व्यवस्था शिमला को स्मार्ट सिटी बनाएगी ?

कूड़े को एकत्रित कर एक स्थान पर ढेर लगाने से समस्या का हल संभव हो ही नहीं

कचरा प्रबन्धनः मात्र कुड़ा एकत्रिकरण नहीं

सकता । अंततः उस कूड़े के ढेर से गंदगी एक बड़े क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेती हैं और कूड़े के ढेर में आग लगने से कई–कई दिनों तक ज़हरीली गैंसों का प्रदूषण वातारण के लिए घातक हो जाता हैं जैसा कि देश के कई स्थानों में हो रहा हैं । एकत्रित कूड़े को रिसाईकल करने अथवा विद्युत बनाने में उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाना होगा

विगत कुछ वर्षों में तो चौंकाने वाली घटनाऐं सामने आई जिसने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी थी । मसलन, सीवरेज का गंद ऊठाउ पेय जल स्रोतों में मिलकर शहरवासियों को बीमार करता रहा, शहर में पेयजल आपूर्ति टैंकों की सफाई व्यवस्था हमेशा से कटघरे में खड़ी रही । जग किरकिरी और हद तो तब हुई जब मासूम युग का नरकंकाल एक पौश इलाक़े में जलापूर्ति टैंक से मिला और पता चला कि महीनों से उसी जल को लोगों को पिलाया गया ।

पानी पर हाहाकार के साथ ही आंकड़ों का खेल भी मज़ेदार हैं । शिमला को पानी मुख्यतः पांच स्रोत हैं : गुम्मा, अश्वनी खड्ड,

शिमला - बनता जा रहा है भारत का केपटाउन

गिरी, चुरटनाला और सियोग । शिमला को

प्रतिदिन के हिसाब से 45 मिलीयन लीटर पानी की आवश्यकता हैं जबकि पानी की उपलब्धता लगभग 18 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही है । इसमें भी 50 प्रतिशत पानी पंपिंग और वितरण के समय लीकेज से बर्बाद हो रहा हैं । शिमला की प्यास बुझाने में सिचांई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के हाथ तो कई बार खड़े हो गए हैं । और यही कारण है कि असफलता के चलते अब वर्ल्ड बैंक से नगर निगम शिमला का समझौता कुछ आशाऐं लेकर आया हैं । 990 करोड़ की इस परियोजना को शिमला में पानी

शिमला में पानी के लिए लंबी कतारों से होकर गुजरना पड़ता है

की क़िल्लत को दूर करने का सपना देखा गया हैं जिसे धरातल पर उतारना अभी शेष हैं । घरों की छतों पर पानी की टंकियों की लीकेज़ एक गंभीर समस्या रही हैं जिस पर सख्ती से कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं

प्रदूषण शिमला की एक अहम समस्या के रुप में सामने है । आईआईटी कानपुर के एक सर्वे के अनुसार मेट्रो सिटीज के अलावा हिल स्टेशन भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है । हिमाचल प्रदेश के के छः ज़िलों को तो सर्वे में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर बताया गया है । यह सर्वे 2011 से 2015 के मध्य का है । प्रदूषण के इस स्तर के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य, खुले में कूड़े को जलाना, यातायात और उद्योगों व फैक्टरी के खुलने को जिम्मेवार बताया गया है । हालांकि इन छः ज़िलों में शिमला का नाम अभी नहीं है लेकिन भविष्य के लिए ख़तरे की घंटी तो है ही ।

शिमला को कितनी ही बार अलग–अलग बहानों से नियमों की जंजीरों में जकड़ा गया और फिर स्वार्थ के लिए यदाकदा उन नियमों में ढील देकर निर्माण कार्य करवाए गए । ग्रीन ऐरिया भी इसकी चपेट में आने से नहीं बचा और वहां भी निर्माण कार्य हुए । तो क्या एनजीटी का फैसला शिमला के हक़ में माना जाऐ ? ऐसा लगता तो है क्योंकि यदि बेतरतीब और अंधाधुंध निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सकी, तभी शिमला को बचाया जा सकता है । साथ ही कूड़ा प्रबन्धन जब तक नहीं होता संपूर्ण स्वच्छता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । इसी कूड़े को विद्युत में परिवर्तित कर उर्जा में बदला जा सकता है । बस रहनुमाओं के अथक प्रयासों को दिशा देने की आवश्यकता है । पार्किंग और यातायात को सुनिश्चित करने पर सार्थक पहल करने की आवश्यकता है । विकास बुरा नहीं होता परन्तु विनाश की सान पर किया गया विकास कदापि सुखद अथवा संपन्नता के आवरण से ढका नहीं होता । शिमला को इसके वास्तविक स्वरुप और गरिमा के साथ ही विकासोन्मुख बनाने की आवश्यकता हैं । इस प्रकार पहाड़ों का सीना चीर कर कंकरीट के जंगल खड़े कर देने मात्र से भविष्य ख़तरे के साये में रहेगा । समय रहते न जागे तो दिल्ली तो दूर है ही.....शिमला भी दूर न हो जाए.....

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com

क्या कहती हैं महापौर कुसुम सदरेट

शिमला को बनाएगें आदर्श शहर

शिमला की वर्तमान स्थिति और परिदृश्य में विकास और स्मार्ट सिटी शिमला पर मेयर कुसुम सदरेट ने द रीव टाइम्स को अपनी योजनाओं और रणनीति पर बेबाकी से बताया । मेयर ने माना कि शिमला में समस्याओं को अंबार तो हैं लेकिन उन समस्याओं पर नगर निगम शिमला निदान के लिए प्रयासरत हैं । उन्होंने कहा कि पानी की समस्या गंभीर तो रही लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एमओयू कर इसको समाधान पर लाने में सफलता हासिल की हैं । वर्ल्ड बैंक शिमला को पानी की आपूर्ति और प्रबन्धन के लिए 990 करोड़ रुपये देगा जिसमें चाबा से गुम्मा तक लगभग 12 किलोमीटी पेयजल पाईपलाईन बिछाई जाएगी और पानी को चाबा से गुम्मा में पेयजल स्टोर में डाला जाएगा । इससे लगभग 10 फीसदी पानी की अतिरिक्त मात्रा गुम्मा स्टोर टैंक में बढ़ेगी यानि पहले गुम्मा में 20 से 21 लाख ली. पानी था जो इस योजना के चलने के बाद 31 लाख ली. से अधिक मात्रा हो जाएगी जिससे 24x7 पानी की उपलब्धता शिमला के निवासियों के लिए संभव हो पाएगी । निगम ने जल निगम बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया है जिसका पूरा कामकाज निगम स्वयं संभालेगा । उन्होंने नगर निगम शिमला की उपलब्धि पर बताया कि इस योजना का टैंडर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया है तथा कार्य आरम्भ किया जा रहा हैं । एमओयू क अनुसार 52 प्रतिशत भागीदारी नगर निगम की होगी और 49 प्रतिशत वर्ल्ड बैंक की । किंतु जलापूर्ति प्रबन्धन नगर निगम शिमला ही संभालेगा ।

पानी की उपलब्धता पर भी मेयर ने बताया कि शिमला ग्रामीण की घण्डल पेयजल योजना से भी शिमला को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है । इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष शुरु किया था उसे सरकार ने पूरा कर दिया हैं । साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य की जयराम सरकार ने धन को आड़े नहीं आने दिया जिससे भविष्य में शिमला को पानी की इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

अव्यवस्थित कूड़ा प्रबन्धन पर महापौर ने स्पष्ट कहा कि इस पर निगम कार्य कर रहा है और स्मार्ट सिटी में शिमला का चयन इस समस्या को भी तरतीब तरीके से हल करेगा । भरयाल में जर्मन कंपनी के साथ कूड़े से विद्युत उत्पादन पर निगम के असफल रहने पर महापौर ने बताया कि यह संयत्र तकनीकि ख़राबी के कारण काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके कलपुर्जे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । लेकिन कंपनी को आदेश किए गए हैं कि अतिशीघ्र संयत्र में कार्य आरम्भ कर कूड़े से विद्युत पैदा करने की इस योजना को सुचारु किया जाए । महापौर ने कहा कि वर्तमान नगर निगम ने शहर के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं पर कार्य किया है । स्मार्ट सिटी शिमला का कायाकल्प करेगा जो कि नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धि हैं । उन्होंने कहा कि शहरवासियों की हर समस्या का समाधान निगम प्राथमिकता के साथ करेगा ।

शिमला को एक बेहतर योजना की दरकार है । शिमला में किसी भी सूरत में निर्माण कार्यों पर रोक लगाना बहुत ज़रुरी है । पानी की समस्या को समय रहते ही योजनाबद्ध तरीके से समाधान पर लाने की ज़रुरत हैं ताकि भविष्य में वर्तमान की तरह लोगों को हायतौबा न करनी पड़े । संजौली में अंधाधुंध निर्माण के चलते सारी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है । शिमला अब बसने लायक नहीं रह गया है । इसे पुनः सवांरने और सुधारने की आवश्यकता हैं ।

निधि शर्मा
गृहणी,संजौली,शिमला

शिमला वास्तव में ही बदल गया है । भवनों के निर्माण कार्य में विगत कुछ समय में जिस प्रकार बेतहाशा वृद्धि हुई है.....उससे शिमला अब असुरक्षित एवं अव्यवस्थित सा हो गया है । यातायात और पानी ने रुलाना शुरु कर दिया है । शिमला को पुनः सुंदर बनाने के लिए सरकार और निगम को प्रयास करने चाहिए । इसके लिए जितनी जिम्मेवारी यहां की सरकार और नगर निगम की है, उतनी ही यहां के नागरिकों की भी हैं । हमें अपनी जिम्मेवारी समझने की आवश्यकता हैं ।

प्रेम वर्मा
कुसुंप्टी, शिमला

यह सत्य हैं कि सुंदर शिमला, सुरक्षित शिमला अब बिल्कुल बदल गया है । शिमला गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहा हैं । शिमला के पौश इलाके बढ़ती आबादी और पानी की समस्याओं से परेशान हैं ।

मनमोहन सिंह
संजौली, शिमला

हिमाचल में 20 लाख टर्न ओवर पर जीएसटी समाप्त

27 जुलाई से लागू हुआ फैसला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पहाड़ी प्रदेश हिमाचल को केंद्र की ओर से बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये करने का फैसला हुआ। यह फैसला 27 जुलाई से लागू हो चुका है। हिमाचल के लिए यह फैसला कई मायानों में अहम है।

जीएसटी काउंसिल की ओर से दी गई छूट से हिमाचल के करीब बीस हजार व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र ने जीएसटी में पंजीकरण में छूट देते हुए 10 लाख के टर्नओवर की सीमा को 20 लाख कर दिया है। इससे करीब बीस हजार व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण नहीं करवाना होगा और रिटर्न भरने से भी छुटकारा मिलेगा। यही नहीं जीएसटी रिटर्न में पांच करोड़ तक के काराबारियों को छूट प्रदान करने से 80 फीसदी व्यापारियों को लाभ पहुंचा है।

बैकवर्ड पंचायातें में उद्योगों को स्टेट जीएसटी में 100 फीसदी छूट

सरकार ने प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को राज्य जीएसटी में 20 से लेकर 100 फीसदी तक की छूट दी है। 1 अप्रैल 2018 के बाद अलग–अलग क्षेत्रों में जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, सरकार ने इसी माह मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसले में इन औद्योगिक इकाइयों को राज्य जीएसटी में वार्षिक प्रतिपूर्ति में छूट दी है।

'सी' श्रेणी में ट्राइबल ब्लॉक की बैकवर्ड पंचायतों में स्थापित उद्योगों को दस साल के लिए सौ फीसदी स्टेट जीएसटी में छूट को मंजूरी दी है।

प्रदेश सरकार ने कानूनगो सर्किल, विकास खंडों और ट्राइबल ब्लॉक की बैकवर्ड पंचायतों के क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अलग–अलग श्रेणियों में रखा है।

इसमें 'ए' श्रेणी के क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पांच साल के लिए 20 फीसदी, 'बी' श्रेणी में आठ साल के लिए 50 फीसदी वार्षिक प्रतिपूर्ति की मंजूरी दी है। सी श्रेणी में सौ फीसदी की छूट दी है।

'ए' श्रेणी में सिरमौर जिले की कानूनगो सर्किल माजरा और औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में आने वाला क्षेत्र, कानूनगो सर्किल नाहन और कालाअंब के तहत आने वाला क्षेत्र, जिला सोलन में कानूनगो सर्किल कसौली के क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र परमाणु, नालागढ़ और दून के क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के सर्किल में स्थापित इकाइयों को 20 फीसदी वार्षिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

बी श्रेणी में हैं उद्योग

'बी' श्रेणी में विकास खंड बिलासपुर सदर, घुमारवीं, झंडूता, चंबा के भटियात और चंबा, हमीरपुर की बिझड़ी, नादौन, भोरंज, सुजानपुर, टीहरा, बमसन, कांगड़ा जिले की रैत, नगरोटा बगवां, पंचरुखी, फतेहपुर, लंबागांव, बैजनाथ, नगरोटा सूरियां, देहरा, भवारना, परागपुर, इंदौरा, सुलह और धर्मशाला, कुल्लू जिले में नग्गर–कटराईं और कुल्लू, मंडी में सुंदरनगर, बल्ह, गोपालपुर, द्रंग, चौंतड़ा, धर्मपुर और मंडी सदर, शिमला जिले के ठियोग, मशोबरा, जुब्बल, नारकंडा और बसंतपुर, सिरमौर में राजगढ़, सोलन जिले में कंडाघाट, कुनिहार और सोलन के अलावा ऊना, अंब, गगरेट, हरोली और ढुढला के क्षेत्रों को आठ साल के लिए 35 फीसदी की छूट होगी।

सी श्रेणी में हैं पिछड़े क्षेत्रों में लगे उद्योग-

'सी' श्रेणी में चंबा जिले के ट्राइबल ब्लॉक की बैकवर्ड पंचायत में भरमौर, पांगी, तीसा, सलूणी और मैहला, किन्नौर की कल्पा, पूह और निचार, कुल्लू की आनी, निरमंड और बंजार क्षेत्र में लगे उद्योग शामिल हैं। लाहौल, केलांग, स्पीति और काजा, मंडी के सराज, करसोग और गोहर, शिमला के रोहड़ू, चौपाल, रामपुर, ननखड़ी, सिरमौर के पच्छाद, शिलाई, संगड़ाह में स्थापित इकाइयों को दस साल के लिए सौ फीसदी की वार्षिक प्रतिपूर्ति दी गई है।

प्रदेश में है तीन लाख व्यापारी

प्रदेश में करीब तीन लाख व्यापारी हैं जिनमें से करीब 92 हजार से अधिक व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीकरण करवाया है। प्रदेश में पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों का आंकड़ा मात्र दस फीसदी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दी गई राहत का सीधा लाभ कारोबारियों को मिलेगा।

2019 तक बनकर तैयार होगी रोहतांग टनल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सामरिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण रोहतांग टनल नवंबर, 2019 तक बनकर तैयार होगी और इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। रोहतांग टनल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द ही मनाली–लेह सड़क पर स्थित बारालाचा, तांगलांगला, लाचुंगला में भी टनल बनाई जाएगी। इन टनल को शुरू करने के लिए भी जल्द सर्वे किया जाएगा। हालांकि इस टनल का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। मौसम साफ होते ही वे दोबारा मनाली आएंगे और टनल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतांग टनल सबसे ऊंचाई पर बनने वाली देश की पहली टनल है। टनल निर्माण में सेरी नाला ने काफी अवरोध पैदा किया, नहीं तो चार साल पहले ही टनल बनकर तैयार हो जाती। सेरी नाला में 600 मीटर तक पानी का रिसाव रोकने में चार साल का समय लग गया था। बीआरओ की टीम ने तकनीकी रूप से काम किया है, जो देश मे पहली बार हुआ है।

शिमला के पानी में मिला सिट्रोबेक्टर कोसरी बैक्टीरिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शहर के पेयजल में पीलिया और शरीर के आंतरिक अंगों में इंफेक्शन फैलाने वाला बैक्टीरिया मिला है। न्यू शिमला, फागली और संजौली के नार्थ ओक स्थित पेयजल टैंक से लिए पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। आईजीएमसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार इन पेयजल टैंकों में पीलिया और इंफेक्शन फैलाने वाला सिट्रोबेक्टर बैक्टीरिया पाया गया है।

नाभा की तिब्बती कालोनी और संजौली चौक स्थित सार्वजनिक नल के पानी में भी बीमारियां फैलाने वाला बैक्टीरिया पाया गया है। उधर, चलौंठी के हैंडपंप और बावड़ी से लिए पानी के सैंपल भी फेल हो गए हैं।

संजौली रिजरवायर के सैंपल भी फेल पाए गए हैं। वहीं, यूवी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बावजूद अश्वनी खड्ड स्थित ट्यूबवेल टू के अनट्रीटेड और ट्रीटेड पानी के सैंपल फेल हो गए हैं।

आईजीएमसी के विशेषज्ञों के अनुसार सिट्रोबेक्टर कोसरी बैक्टीरिया न सिर्फ पीलिया फैला सकता है बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों में इंफेक्शन भी फैलाता है। कई बार क्लोरीनेशन के बावजूद पानी में यह बैक्टीरिया रह जाता है। ऐसे में पानी उबालकर ही पीएं।

सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद् को मिलेगा एक करोड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद् को एक करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश के शहरी निकायों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जयराम ठाकुर सरकार ने श्रेष्ठ शहर योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को एक करोड़ रुपये तथा नगर पंचायत को 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

25 निकाय खुला शौच मुक्त निकायों की होगी स्टार रैंकिंग

प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 25 खुला शौच मुक्त घोषित कर दिए हैं। जल्द ही 10 और 11 अन्य शहरी निकाय भी खुला शौच मुक्त हो जाएंगे।

अब प्रदेश में सबसे सुंदर, साफ–सुथरे तथा स्वच्छ शहरी निकायों की तीन से सात स्टार तक रैंकिंग की जाएगी। जो शहरी निकाय सबसे साफ, सुंदर और स्वच्छ होंगे उन्हें भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय स्टार रैंकिंग देगा।

सरकार ने 487 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया

चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी विकास विभाग के लिए सरकार ने 487 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस मौके पर सरवीण चौधरी ने ऊना और हमीरपुर जिलों के 17 स्वयं सहायता समूहों को बतौर रिवोलविंग फंड के चेक वितरित किए।

कोटी वन कटान मामला

आरोपी की संपत्ति बेच 34.50 लाख रुपये वसूलने के आदेश

टीम टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल हाईकोर्ट ने जनवरी में कोटी वन रेंज में हुए 416 पेड़ों के कटान मामले में आरोपी भूप सिंह और उसके परिवार की संपत्ति बेचकर साढ़े 34 लाख की वसूली करने के आदेश दिए हैं। यह रकम काटे गए पेड़ों की कीमत के रूप में आंकी गई है, जिसे कथित तौर पर भूप सिंह ने अवैध खनन को काटे थे। कोर्ट ने वसूली जाने वाली राशि का 50 फीसदी हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। शेष राशि जमानत के रूप में सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस काम का जिम्मा डीसी शिमला को सौंपा।

श्रीखंड महादेव की यात्रा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। उसके बाद अमरनाथ यात्रा का नंबर आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन है। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18570 फीट ऊचाई पर चढ़ना होता है।

श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। इसके शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है। श्रीखण्ड महादेव की 35 किलोमीटर की इतनी कठिन चढ़ाई है, जिसपर कोई खच्चर घोड़ा नहीं चल ही नहीं सकता। श्रीखण्ड का रास्ता रामपुर बुशैहर से जाता है। यहां से निरमण्ड, उसके बाद बागीपुल और आखिर में जांव के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है।

क्या है पौराणिक महत्व- श्रीखंड की पौराणिकता मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से शिव से वरदान मांगा था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रखेगा तो वह भस्म होगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए भस्मापुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उसे भस्म करने की योजना बनाई लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी मंशा को नष्ट किया। विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख लिया और भस्म हो गया। आज भी वहां की मिट्टी व पानी दूर से लाल दिखाई देते हैं।

शिमला में होगा मिस्टर हिमाचल 2018 का मुकाबला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

19 अगस्त 2018 को गेयटी थिएटर, शिमला में होगा मिस्टर हिमाचल चौंपियनशिप 2018 का आयोजन, इस प्रतियोगिता के लिए हिमाचल के प्रत्येक हिस्से के खिलाड़ी पूरे जोश से तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता के आयोजक राहुल नेगी ने जानकारी देते हुए बताया की गेयटी में होने वाले आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। प्रतियोगिता में राज्य के करीब 200 उत्कृष्ट खिलाड़ी, शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन करने वाले हैंद्य प्रतियोगिता को चार वर्गों में विभाजित किया गया हैद्य बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मॉडलिंग व फैशन मॉडलिंग जिसमें खिलाड़ी पुरुष व महिला वर्गों में भाग लेंगे।

प्रतियोगिता का खास आकर्षण हिमाचल में प्रथम बार दिव्यांग बॉडीबिल्डर के बीच होने वाला मुकाबला होगा। IFBB ग्लोबल शिमला के अध्यक्ष दीक्षित मल्होत्रा ने बताया की दिव्यांग बॉडीबिल्डर के लिए हिमाचल में यह इस तरह का प्रथम प्रयास है।

पांच रोप वे के टेंडर दोबारा करने की तैयारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल की पांच बड़ी रोप–वे परियोजनाओं के लिए जयराम सरकार दोबारा टेंडर करेगी। दियोटसिद्ध–शाहतलाई, टोबा–नयनादेवी, भरमौर–भरमाणी माता, न्यूगल–पालमपुर तथा सराहन–बाशल कांडा की प्रस्तावित परियोजनाएं काफी समय से लंबित है।

पठानकोट से उड़ा मिग-21 हिमाचल में क्रैश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पंजाब के पठानकोट एयरबेस से बीते 18 जुलाई को दोपहर 12:20 बजे टेक ऑफ करने के बाद इंडियन एयरफोर्स मिग–21 फाइटर प्लेन थोड़ी ही देर बाद 01:21 बजे कांगड़ा के फतेहपुर की पट्टा जातियां पंचायत के झुलाड़ गांव में क्रैश हो गया।

जिस जगह विमान क्रैश हुआ, वहां 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। आधा किलोमीटर तक विमान का मलबा फैला हुआ है। पायलट की पहचान स्क्वाड्रन लीडर मीत कुमार निवासी दिल्ली के रूप में हुई।

हिमाचली लहसुन इजराइल में सर्वश्रेष्ठ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के सोलन से इजराइल ने पहली बार लहसुन आयात किया। पहली ही बार में सोलन के लहसुन को इजराइल ने सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे पहले 2017 में फिक्की ने भी हिमाचल के लहुसन का परीक्षण कर इसे सर्वश्रेष्ठ बताया था।

नवंबर मोबाइल पर बिजली बिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में नवंबर महीने से बिजली बिल मोबाइल फोन पर मिलेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन हिमाचल में 95 फीसदी बिलिंग को ऑनलाइन करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था से हर माह की पांच तारीख तक पता चल जाएगा कि कितनी बिजली खर्च की गई? कितना बिल आया है?

बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है? उपभोक्ता भारत पे बिल एप के जरिये बिजली बिल की अदायगी भी कर सकेंगे। इस योजना को भारत बिल पे सिस्टम से जोड़ा जाना है। मोबाइल पर घर बैठे ले सकेंगे अपने बिल की जानकारी इस सिस्टम पर 75 से अधिक बैंक जुड़े हुए हैं। हिमाचल में ऑनलाइन बिलिंग शुरू होने से उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल फोन पर अपने बिल से संबंधित जानकारी ले सक

संजय कुंडू मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

1989 बैच के आइपीएस अधिकारी संजय कुंडू को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वह क्वालिटी कंट्रोल सेल देखने के साथ केंद्रीय प्रोजेक्टों की निगरानी रखेंगे।

इस पद पर पहली बार किसी अधिकारी की तैनाती की गई है। संजय कुंडू को डीजीपी नहीं बनाया गया है लेकिन इससे कम पद भी नहीं दिया गया है।

शिमला में ढाई मंजिल से ज्यादा निर्माण को एनजीटी की ना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। एनजीटी ने शिमला में ढाई मंजिल से ऊपर भवन निर्माण पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसे लेकर सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को एनजीटी ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने शिमला प्लानिंग एरिया को लेकर पहले दिए अपने आदेशों में भी कोई तबदीली नहीं की है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार एनजीटी की उच्च स्तरीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकती है।

16 नंवबर 2017 को सुनाया था फैसला

एनजीटी ने 16 नंवबर 2017 को इस मसले पर विस्तार से फैसला सुनाया था। फैसले में कहा था कि शिमला और प्लानिंग एरिया के भीतर ढाई मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत नहीं बनाई जा सकती है। पीठ ने हाईव लेवल कमेटी बनाई थी, जिसमें एक निगरानी और दूसरी कार्यान्वयन समिति शामिल है। बाद में हिमाचल सरकार ने फैसले में समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी।

ये प्रावधान किए थे

एनजीटी ने आदेशों में कहा था कि पर्यावरण क्षति पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही निगरानी और कार्यान्वयन समिति हर महीने बैठक करेगी। शिमला में बिना मंजूरी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हर पुराने और नए भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा।

टब फोरेस्ट और ग्रीन एरिया और कोर एरिया में 16 नवंबर 2017 के बाद से निर्माण की मंजूरी नहीं होगी। पहले बने निजी और व्यावसायिक भवन यदि नक्शे और एनओसी के अनुरूप होंगे, तभी उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि नक्शे से ज्यादा विस्तार के लिए निजी घर के लिए 5 हजार प्रति वर्ग फीट और व्यावसायिक संरचना के लिए 10 हजार प्रति वर्ग फीट क्षतिपूर्ति देनी होगी। बताया जा रहा है कि सरकार की याचिका खारिज होने के बाद अब सरकार इस मामले में कानूनी सलाह मशविरा कर ही है।

बैंक तक अब ऑनलाइन पहुंचेगी जमाबंदी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जमीन पर लोन लेने से पहले जमाबंदी हासिल करने के लिए लोगों को अब राजस्व व बैंक अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैंक में लोन के लिए जमीन की जानकारी देने के बाद ऑनलाइन ही बैंक जमाबंदी के लिए राजस्व विभाग को आवेदन कर देंगे। इसके बाद राजस्व अधिकारी भी ऑनलाइन जमीन के विवरण के साथ जमाबंदी जारी कर देंगे।

राजस्व विभाग ने बैंकों और एनआईसी के साथ मिलकर इसके लिए नया पोर्टल तैयार किया है।

बैंक में लोन के आवेदन के बाद आवेदक को पटवारी से जमाबंदी लानी होती थी। इसमें यह विवरण होता था कि जमीन कितनी है, किसके नाम है और उस पर पहले से कोई लोन तो नहीं है। जमाबंदी के लिए लोगों के लेखपालों के कई दिन चक्कर काटने पड़ते थे।

लोगों को नहीं लगाने होंगे राजस्व अधिकारी के चक्कर

इसके बाद इसे बैंक में जमा कराना होता था जिसके आधार पर बैंक लोन रिलीज करते थे। लोगों की इसी दिक्कत को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने पर चर्चा हुई।

इसके बाद राजस्व विभाग ने बैंकों और एनआईसी के साथ मिलकर ऑनलाइन चार्ज बनाने के लिए पोर्टल तैयार किया। अब लोन के आवेदन के बाद बैंक ऑनलाइन ही राजस्व विभाग को जमाबंदी के लिए आवेदन कर देगा।

तीन जिलों के लिए जलसंरक्षण योजना

708.87 करोड़ की पहली किस्त जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

परियोजना के लिए केंद्र ने 708.87 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

इस परियोजना के लिए तीन जिलों मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों का चयन किया गया है। यह परियोजना 4751 करोड़ रुपये की है। इसकी यह पहली किस्त जारी हुई है।

पहले चरण में यह परियोजना जल की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इनमें मंडी जिले के धर्मपुर, लड़भड़ोल और थुनाग, हमीरपुर जिले के बमसन, सुजानपुर और बिलासपुर जिले के घुमारवीं में 708.87 करोड़ रुपये के विभिन्न जल सरंक्षण कार्य किए जाएंगे।

वर्ष 2017 तक 2.691 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं जबकि 65,885 हेक्टेयर क्षेत्र पर अभी भी सिंचाई सुविधाएं

उपलब्ध नहीं हैं।

परियोजना के माध्यम से मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में विकास के स्रोतों पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक 2.691 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं जबकि 65,885 हेक्टेयर क्षेत्र पर अभी भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, मक्की और धान का उत्पादन बढ़ाकर इसे विश्व स्तर की फसल उत्पादकता के बराबर ले जाना है।

नामी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रवृति

योजना शुरू करने वाला हिमाचल 15वां राज्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देश के नामी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। 26 जुलाई को प्रदेश में सबल भारत छात्रवृत्ति योजना लांच होगी। इसे शुरू करते ही हिमाचल देश का 15वां राज्य बन जाएगा। सबल छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर विद्यार्थी देश के किसी भी नामी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पा सकेंगे। यह छात्रवृत्ति न केवल उच्च शिक्षा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा और खेल प्रशिक्षण के लिए भी मिलेगी।

हिमाचल में सबल भारत योजना की मॉनीटरिंग का जिम्मा प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग एंड न्यू इनेशेटिव कमेटी को दिया गया है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय योजना के लिए बजट मुहैया करवाएगा। योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर की होगी परीक्षा

प्रारंभिक स्तर से उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देनी होगी।

अंकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 27 जुलाई से हिमाचल में परीक्षा में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर

तीन दिन में सवा तीन लाख पौधे रोप कर मंडी अव्वल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पौधा रोपण प्रतियोगिता में मंडी ने 336108 पौधे रोप कर पहला स्थान प्राप्त किया जबकि जिला शिमला का रामपुर वृत दूसरे स्थान पर रहा। मंडी में कुल 106 जगहों पर 399 हेक्टेयर पर पौधा रोपण किया गया।

नशे पर लगाम और किसानों को राहत के लिए कसरत तेज

मंत्रीमंडल की बैठक में कई अहम फैसले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जुलाई माह के आखरी सप्ताह में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में युवाओं को स्वरोजगार देने के साथ साथ युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वहीं किसानों को भी राहत दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के लिए योजना को भी मंजूरी दी गई।

नशे पर लगाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स

हिमाचल में बढ़ते नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए तस्करों की धरपकड़ के लिए प्रदेश स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित की जाएगी। एसटीएफ प्रदेश भर में कहीं भी नशीले पदार्थ की तस्करी या किसी नामी तस्कर की सूचना पर कार्रवाई करने में सक्षम होगी। मंत्रिमंडल ने एनडीपीएस एक्ट में कई तरह के संशोधनों की पुलिस की दलील पर सहमति जताई। साथ ही एक्ट में कई बदलावों को करने के लिए मंजूरी दी।

किसानों के लिए राहत

सोलर फेसिंग पर 80 से 85 फीसदी छूट

हिमाचल में अगर तीन से ज्यादा किसान सोलर फेंसिंग करेंगे तो उन्हें 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। कोई व्यक्तिगत तौर पर सोलर फेंसिंग करना चाहे तो उसे 80 फीसदी उपदान मिलेगा। हिमाचल में किसानों को राहत देने के लिए राज्य में 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' और 'मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना' के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के तहत किसानों को पॉलीहाउसों की क्षतिग्रस्त पॉलीशीट बदलने को 50 प्रतिशत के वर्तमान अनुदान के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान मिलेगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में करीब पांच लाख चयनित परिवारों का पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए आयुशमान भारत – प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लागू करने करने को मंजूरी दे दी।

इन चयनित परिवारों का इलाज करवाने के लिए 175 अस्पतालों को चुना गया है। इस स्कीम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में हाल ही में लांच किया था। इसके साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त या सेवानिवृत्त संबद्धता प्राप्त पत्रकारों को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में वित्तीय सहायता बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। उन्हें मौजूदा 50 हजार रुपये के बजाय ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

चंबा में डुग्गर प्रोजेक्ट एनएचपीसी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार ने पांगी में 449 मेगावाट की क्षमता वाला डुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) को सौंप दिया है।

को 70 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर एनएचपीसी को देने का फैसला लिया गया। निर्धारित अवधि के बाद प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के अधीन आ जाएगा।

यह प्रोजेक्ट का चंबा के पांगी में चिनाब नदी पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

जीएसटी को लेकर कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

कैबिनेट ने प्रथम जुलाई, 2017 से पूर्व चल रहे ठेके के कार्यों के लिए जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ठेकेदारों का मनोबल बढ़ाने के लिये तथा कार्यों को जल्द पूरा करने के लिये 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यों के लिये प्रमाणित बोली दस्तावेज में प्रोत्साहन उप–नियम लागू करने का निर्णय लिया।

ठेकेदारों को निर्माण स्थल पर मलबे को उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करने के लिए क्रशर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि सामग्री को निर्माण कार्यों में पुनः उपयोग में लाया जा सके।

चीड़ पत्ती उद्योग में निवश पर 50 फीसदी छूटके लिए नीति को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित चीड़ पत्ती उद्योग के लिए नीति को मंजूरी दे दी है। वन विभाग विभिन्न माध्यमों से इन चीड़ के पेड़ों से गिरी पत्तियों को इकट्ठा कर संबंधित उद्योगों को उपलब्ध कराएगा, जो इसका उपयोग विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार करने में करेंगे।

बैठक में इस बात को भी मंजूरी दी गई कि निवेश करने वाले उद्योगों को पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जंगलों में लगने वाली आग में अगले साल कमी आएगी और चीड़ पत्ती से जुड़े नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 31 अगस्त तकप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 23 से 31 अगस्त बुलाया जाएगा। इस बार मानसून सत्र में कुल सात बैठकें होंगी। सात दिन तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान सात बैठकें होंगी। सत्र में सरकारी और गैर सरकारी संकल्प भी लाए जाएंगे।

बाइक और मैक्सी कैब किराये पर देने के लिए लाइसेंस

हिमाचल के पर्यटन स्थलों और बाहरी राज्यों के लिए बाइक और मैक्सी कैब किराये पर देने के लिए सरकार लोगों को लाइसेंस देगी। अभी लोग अपना कारोबार करने के लिए पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को किराये पर मोटरसाइकिल और मैक्सी कैब उपलब्ध कराते रहे हैं।

अब इसके चलते सरकार ने लाइसेंस लेने की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।

अब गरीबों के आवास के लिए मिलेगा 1.30 लाख

हिमाचल में गरीब रेखा से नीचे रह रहे लोगों के आवास को 1.30 लाख रुपये की राशि मिल पाएगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। इस योजना के मुताबिक सरकार ने 42 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रखा है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को आवास सहायता प्रदान की जाएगी।

युवाओं को स्वरोजगार पर अब 25 फीसदी उपदान देगी सरकार

प्रदेश में सेवा और व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जयराम मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना लागू करने को मंजूरी दे दी। इस योजना से प्रदेश के 18 से 35 साल के युवाओं को लाभ मिलेगा। योजना में खुदरा व्यापार अथवा दुकान, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, साहसिक पर्यटन, परंपरागत शिल्प जैसे कार्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना का एलान किया था।

योजना में व्यापार तथा सेवा कार्य शुरू करने के लिए जमीन और भवन क्रय पर वर्तमान 6 प्रतिशत की बजाय तीन प्रतिशत की दर से स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। यही नहीं, भूमि और मकान को छोड़कर तीस लाख तक के निवेश पर 25 प्रतिशत उपदान सरकार देगी।

सरकार के इस फेसले से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीर जगी हैं।

रूस में एक लाख से ज्यादा बच्चे सीख रहे शास्त्रीय -नृत्य

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति रूस में बढ़ रहा है रूझान, भारतीय दूतावास दे रहा है प्रोत्साहन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हरियाणा के धर्मेंद्र गौतम को कराटे का शौक था, लेकिन पिता के कहने पर शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू किया और आज उनके इशारों पर रूस के एक लाख से ज्यादा बच्चे नृत्य सीख रहे हैं। भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में गुरु धर्मेंद्र की शिष्याओं ने कत्थक, लावणी और घूमर नृत्य पेश किए।

ये सभी लड़कियां रूसी ही थीं और मेकअप में पहचानना मुश्किल हो रहा था कि भारतीय लग रही थीं। धर्मेंद्र गौतम करीब तीन साल से यहां हैं और भारतीय दूतावास की तरफ से मास्को सहित रूस के अन्य शहरों में भी बच्चों को नृत्य सिखा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अकेले मास्को में ही अस्सी से ज्यादा युवतियां सीख रही हैं, इनमें एक ही लड़का है। मास्को में रोज 11 बजे से 7 बजे तक अभ्यास कराया जाता है। इनसे फीस नहीं ली जाती है, भारत सरकार ही खर्च उठाती है। हफ्ते में पांच दिन मास्को में और बाकी दो दिन रूस के दूसरे शहरों में बच्चों को सिखाते हैं।

रूस में ओडिसी नृत्य को लेकर ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए उसके छात्र ज्यादा हैं। भारत में भी इन बच्चों ने अपनी कला दिखाई है। ये लोग हिंदी गानों पर नाच करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कुछ ऐसे गाने भी लिए गए हैं, जिनमें लोक संगीत हो और शास्त्रीय संगीत भी। घूमर नृत्य यहां इन दिनों ज्यादा चल रहा है।

मास्को में तो फिर भी ठीक है, और शहरों में इतने बच्चे आ जाते हैं कि सभी को शामिल नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसे भी हैं, जो दूसरे शहरों से यहां मास्को आकर सीख रहे हैं कि यहां प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है।

गुरु धर्मेंद्र गौतम ने पंडित बिरजू महाराज के साथ संजय लीला भंसाली की 'देवदास' में पढ़ंत की थी और नृत्य निर्देशन में भी हिस्सेदारी की थी। अब उनका मन है कि यहीं मास्को में खुद ही नृत्यशाला शुरू करें। भारत सरकार से उन्हें पूरी मदद और सुविधा मिल रही है, लेकिन फिर भी अपनी नृत्यशाला में वे खुल कर मन की कर सकेंगे। इन लड़कियों का नृत्य देख कर लगा, रूस में शास्त्रीय नृत्य के अच्छे दिन नजदीक ही हैं।

90 दिन तक माही के साथ दुनिया नापने निकली दो बेटियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो

20 साल की दो महिला पायलट ने बेटियों के सम्मान के लिए 90 दिन में दुनिया नापने का बीड़ा उठाया है। इस साहसिक मिशन की कमान आरोही पंडित के हाथ होगी और उनके साथ छोटे से लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में होंगी कीथर मिसविक्टा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस मुहिम में उन्हें सहयोग कर रहा है। बेटियों को सम्मान दिलाने का संदेश फैलाने वाले उनके एयरक्राफ्ट पर लिखा होगा–बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।

विमान को पटियाला से 30 जुलाई को रवाना किया गया। करेंगी। मंत्रालय उनके मार्ग में आने वाले देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के जरिये उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करेगा। यदि सब कुछ तय समय सीमा और योजना के अनुसार हुआ, तो दोनों महिला पायलट 90 दिनों में तीन महाद्वीपों के 23 देशों से होते हुए लगभग 40,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि भारत की दो युवा बेटियां अपने हौसलों की उड़ान से देश की बेटियों को सशक्त बनाने की एक सच्ची मिसाल पेश करेंगी। आरोही ने बताया कि लगभग चार साल से वह व कीथर दोस्त हैं। दोनों ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में भी साथ–साथ प्रशिक्षण लिया। उन्हें इस विमान पर लगभग 40 घंटे उड़ान भरने का अनुभव हैं। लिहाजा जब उन्हें इस अभियान का पता चला तो दोनों ने एक टीम के रूप में मिलकर काम करने का फैसला किया।

रोज चार घंटे ही उड़ सकता है

स्लोवेनियाई निर्मित माही नामक यह जहाज प्रतिदिन चार घंटे ही उड़ सकता है और इसकी उड़ान पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। आपात स्थिति में आरोही और कीथर बैलिस्टिक पैराशूट का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसकी मदद से पूरा विमान ही सुरक्षित नीचे उतर आएगा। दोनों कप्तानों को उम्मीद है कि उन्हें इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान की अधिकतम गति क्षमता 215 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए इस अभियान में दोनों महिलाओं को कई जगह रुकना पड़ेगा।

आखिर क्यों पीएम मोदी ने रवांडा को दीं 200 गायें, जानें क्या है इसका महत्व

पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा में रवांडा को 200 गायें दी हैं। भारत सरकार के इस फैसले की चर्चा हो रही है। दरअसल इस फैसले के पीछे रवांडा सरकार की ओर से चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार वहां पर कुपोषण दूर करने के लिये 3.50 लाख गांवों को गाय देगी और फिर उसके पैदा हुई एक बछिया को वह अपने पड़ोसी को देगा। इस योजना का मकसद इन गायों के दूध से परिवार अपने बच्चों का कुपोषण दूर करेंगे साथ ही दुग्ध उद्योग को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

रवांडा में गाय को माना जाता है समृद्धि का प्रतीक

भारत की तरह ही रवांडा में भी गाय को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रवांडा के प्राचीन इतिहास में गाय को मुद्रा की तरह प्रयोग में लाया जाता था। आपको बता दें कि भारत की तरह रवांडा भी कृषि प्रधान देश है। यहां की 80 फीसदी खेती से जुड़ी है। रवांडा की आबादी 1.12 करोड़ है यहां की संसद में 2 तिहाई महिला सांसद हैं।

पृथ्वी के इतिहास की नई खोज भूवैज्ञानिकों ने खोजा मेघालय युग

पृथ्वी पर न जाने कितने लाखों–करोड़ों वर्षों की संस्कृति के सबूत मिलते रहते है और वैज्ञानिक इन तथ्यों का अनवेषण कर नए रहस्यों का पता लगाते हैं। भूवैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग की खोज की है और खास बात यह है कि इसका भारत के मेघालय से कनेक्शन है। वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को 'मेघालय काल' का नाम दिया है। इस दौरान विश्व भर में अचानक भयंकर सूखा पड़ा था और तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी। इस वजह से पूरे विश्व में कई सभ्यताएं खत्म हो गईं थीं। अब सवाल यह है कि आखिर इसका नाम मेघालय युग क्यों रखा गया?

दरअसल शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने मेघालय की एक गुफा की छत से टपक कर फर्श पर जमा हुए चूने के ढेर या स्टैलैगमाइट को जमा किया। इसने धरती के इतिहास में घटी सबसे छोटी जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद की। इस वजह से इस मेघालयन एज या मेघालय काल का नाम दिया गया। 4.6 अरब साल के धरती के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है। हर कालखंड महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे महाद्वीपों का टूटना, पर्यावरण में नाटकीय बदलाव या धरती पर खास तरह के जानवरों, पौधों की उत्पत्ति पर आधारित है। जिस वर्तमान काल में हम रहे हैं उसे होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें पिछले 11700 सालों का इतिहास शामिल है, तब से जम मौसम में पैदा हुई एक नाटकीय गर्मी से हम हिम युग से बाहर आए थे।

हालांकि इंटरनैशनल कमिशन ऑफ स्ट्रैटिग्रफी (आईसीएस) के मुताबिक होलोसीन युग को भी बांटा जा सकता है। भूवैज्ञानिक इतिहास और समय का आधिकारिक ब्योरा रखने की जिम्मेदारी आईसीएस की ही है। इसने युग को अपर, मिडल और लोअर चरणों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है। इन सबमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। इनमें सबसे युवा 'मेघालय युग' 4200 साल पहले से लेकर 1950 तक माना जाता है। इसकी शुरुआत भयंकर सूखे से हुई थी, जिसका असर दो शताब्दियों तक रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतिम हिम युग की समाप्ति के बाद कई क्षेत्रों में विकसित हुए कृषि आधारित समाज पर इस मौसमी घटना ने गंभीर प्रभाव डाला था। इसके परिणामस्वरूप मिस्र, यूनान, सीरिया, फलस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांग्त्से नदी घाटी में सभ्यताएं प्रभावित हुईं।

नजरिया: अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की ओर अहम कदम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने मानव मिशन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम है। क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष अभियान को रोके जाने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से निकलने में मदद करेगा। इससे पहले सिर्फ तीन देशों– अमरीका, रूस और चीन के पास इस तरह की सुविधा है।

इसरो का यह परीक्षण कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को इससे क्या उपलब्धि हासिल हुई और मानव मिशन की दिशा में इसे बड़ी सफलता क्यों कहा जा रहा है?

ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, इसका पता लग चुका है

जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं?

उत्तर है– पृथ्वी पर जितने समुद्री तट हैं और वहां जितने बालू के कण हैं, उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं।

यह दावा है अमरीका खगोलविद कार्ल सगन का उन्होंने यह बात एक टीवी शो में कही है।

लेकिन क्या उनका दावा सही है? क्या ब्रह्मांड के तारों की गिनती की जा सकती है?

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद प्रोफेसर गैरी गिरमोर हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की गिनती कर रहे हैं। आकाशगंगा में ही पृथ्वी और सौर मंडल है।

आकाशगंगा में 20 हजार करोड़ तारे

उन्होंने बीबीसी से कहा, दूरी के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहला डेटा जारी किया है, उसमें 2 अरब से कम तारे हैं। यह हमारे आकाशगंगा के कुल तारों का महज एक फीसदी है। लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा की बात है। फिर पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे?

ब्रह्मांड में 10 हजार करोड़ आकाशगंगा हैं

ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या पता लगाने से पहले यह पता लगाना होगा कि यह कितना चमकीला है।

क्या अन्य सभी हमारी आकाशगंगा की तरह हैं या फिर हमसे अलग हैं?

प्रोफेसर गैरी गिरमोर कहते हैं, यह पता लगाने के लिए हमें आकाशगंगा की दूरी और आकार का पता लगाना होगा। इसे हबल लॉ कहते हैं। हबल लॉ की मदद से प्रोफेसर गैरी आकाशगंगा की चमक और हमसे उसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में 10 हजार करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20 हजार करोड़ तारे हैं। अब इन संख्याओं का गुणा करके ब्रह्मांड में तारों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। यानी दो के बाद 22 शून्य होंगे।

समय से पहले 2019 का आम चुनाव कराना चुनौती!

द रीव टाइम्स ब्यूरो

2019 में प्रस्तावित आम चुनाव समय से पहले करवाना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव दिख रहा है, क्योंकि चुनाव के लिए VVPAT समय पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

2019 Elections: 19 जून तक तय लक्ष्य का सिर्फ 22 फीसदी ही VVPAT डिलीवर किया गया है, ऐसे में समय से पहले चुनाव मुश्किल है।

खास बातें

- समय से पहले आम चुनाव होने की चल रही थी चर्चा
- लेकिन VVPAT की डिलीवरी में देरी से नहीं हो सकेगा चुनाव
- अभी तक तय लक्ष्य का सिर्फ 22 फीसदी ही VVPAT डिलीवर

2019 में प्रस्तावित आम चुनाव को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच बड़ी खबर आ रही है. पहले कहा जा रहा था कि आम चुनाव समय से पहले हो सकता है, लेकिन अब चुनाव समय से पहले करवाना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव दिख रहा है. क्योंकि चुनाव के लिए VVPAT समय पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर ने सूचना के अधिकार त्ज्प् के तहत हासिल की है। चुनाव आयोग ने VVPAT, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के लिए दो कंपनियों को पिछले साल सितंबर में ऑर्डर दिए थे, जिनकी डिलीवरी इसी साल सितंबर तक होनी थी, लेकिन ये कंपनियां इस लक्ष्य को पाने में नाकाम रही है. 19 जून तक तय लक्ष्य का सिर्फ 22 फीसदी ही टटच्।ज डिलीवर किया गया है. ऐसे में VVPAT डिलीवरी में देरी होनी तय है। जिसकी वजह से समय से पहले चुनाव कराना असंभव नजर आ रहा है। NDTV ने जब इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और NDTV की डिलीवरी में देरी हुई है, लेकिन नवंबर तक सारी VVPAT मशीनें डिलीवर हो जाएंगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि डिलीवरी में केवल डेढ़ महीने की देरी होगी। दो कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें से एक कंपनी 7 नवंबर और दूसरी कंपनी 15 नवंबर तक मशीनें डिलीवर कर देगी. आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग को सितंबर 2018 तक 40 लाख वीवीपैट मशीनें व ईवीएम मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल 2019 के आम चुनावों में होगा। केंद्र ने निर्वाचन आयोग को 40 लाख मशीनों की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा था कि हमें 23 लाख से ज्यादा ईवीएम व 16 लाख वीवीपैट मशीनों की जरूरत 2019 के चुनावों के लिए है। गौरतलब है कि वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी होती हैं, जिसमें एक मतदाता द्वारा मतदान करने पर उम्मीदवार का नाम व जिस पार्टी के पक्ष में उसने वोट डाला है उसके चुनाव चिन्ह की पर्ची आती है।

VVPAT के मामले में कब -कब क्या हुआ

- 19 अप्रैल 2017 – 2019 चुनावों के लिए 16.15 लाख VVPAT खरीद को मंजूरी
- 24 अप्रैल 2017 – BEL/ ECIL सितंबर 2018 तक डिलीवर करेगा चुनाव आयोग
- 6 सितंबर 2017 – BEL/ ECIL के साथ चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक
- 19 सितंबर 2017– चुनाव आयोग ने ECIL का आधा ऑर्डर BEL को दिया
- 8 दिसंबर 2017–आयोग ने रक्षा मंत्रालय, एटोमिक एनर्जी विभाग से समय पर काम पूरा न होने की आशंका जताई
- 18 दिसंबर 2017 – स्थिति से और बेहतर निपटा जा सकता था– चुनाव आयोग से अधिकारी
- 31 मार्च 2018 – ECIL लक्ष्य से चूका, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट की डिलीवरी नहीं.
- 31 मार्च 2018 –केवल 53,500 VVPAT की डिलीवरी हुई
- 31 मार्च 2018 – BEL ने 1.4 लाख बैलेट यूनिट, 1.4 लाख कंट्रोल यूनिट, 2. 24 लाख VVPAT की डिलीवरी दी
- 17 अप्रैल 2018– समीक्षा बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा–ECIL प्रदर्शन नहीं सुधार रहा
- 5 जून 2018– चुनाव आयोग की BEL/ECIL के साथ समीक्षा बैठक, नाखुशी जताई

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- उद्योग नहीं, लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि लोगों की जान किसी भी उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की जान से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत संबंधी रिपोर्ट देखने के बाद की।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सरकार से पूछा है कि पेट कोक के आयात की इजाजत क्या लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किए बिना दी गई थी। पीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध लगाने से होने वाले प्रभाव के बारे में स्टडी करने के लिए और समय मांगने पर खिंचाई भी की।

पीठ ने सरकार से कहा, ऐसा लगता है कि आप पेट कोक के आयात की इजाजत देने के लिए तत्पर हैं। क्या पूर्व में पेट कोक के आयात की इजाजत देते वक्त लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले असर का अध्ययन किया था।

अखबारों में एक रिपोर्ट आई थी कि प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। पीठ ने सरकार से पूछा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? राजधानी में प्रदूषण की वजह से लोग मर रहे हैं। हम नहीं जानते कि यह रिपोर्ट सही है या नहीं, लेकिन आपकी रिपोर्ट में यह इशारा किया गया था कि प्रदूषण के कारण लोगों की जान जा रही है। पीठ ने कहा कि लोगों की जान किसी भी उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है।

वहीं इस मामले में अमाइकस क्यूरी वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध का समर्थन किया है, लेकिन पर्यावरण व वन मंत्रालय ने विरोध किया था। वहीं, सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की जान किसी और चीज से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने पीठ से कहा कि उन्हें विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का वक्त दिया जाए। इसके बाद पीठ ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर बैठक कर अदालत को विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट से सौंपने को कहा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया प्रदूषण रोकने का प्लान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने आने वाले सालों में बीएस.6 ईंधन की गाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। यह जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि देशभर के बाजार में पहली अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस.6 की गाड़ियां ही बिकेंगी। वहीं जो गाड़ियां बीएस. 6 ईंधन युक्त नहीं होंगी वे 31 मार्च, 2020 तक ही बिक सकेंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के लिए डीजल की कीमतों को अलग–अलग नहीं रखा जा सकता है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट पोल्युशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन कमेटी (ईपीसीए) से पूछा कि क्या पहचान के लिए पेट्रोल, डीजल बीएस. 3,4 और 6 के लिए अलग–अलग रंग के स्टीकर जारी किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत बीएस.6 से की जा सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बीएस.6 गाड़ियों के नंबर प्लेट का अलग रंग हो, जिससे इनकी पहचान हो सके। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दिल्ली में टैक्सी की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली में अलग–अलग रंगों के साथ ओला और उबर की कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। इसके जवाब में सरकार ने कोर्ट को बताया कि लगभग 68 हजार गाड़िया टैक्सी में चल रही हैं। ईपीसीए की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर सीएनजी चालित हैं, लेकिन निजी वाहनों के साथ ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दिल्ली के टैक्सी वालों को बीएस.6 गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ राहत या लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चरम पर हैं तथा इस पर सरकार और सामाजिक संस्थाऐं समय– समय पर चिंता तो व्यक्त करती है किंतु समाधान न के बराबर है

घर की सीलन आपको कर सकती है बीमार हो सकता है श्वास संबंधी रोग

घर में पानी के रिसाव और उससे होने वाली सीलन को कभी पनपने नहीं देना चाहिए।

घर की सीलन से हो सकता है अस्थमा।

घर में मौजूद दीवारो की सीलन को आमतौर पर हम गम्भीरता से नहीं लेते, लेकिन यह जानने के बाद की घर में किसी भी रूप में मौजूद सीलन श्वास संबंधी गम्भीर रोगों को जन्म दे सकती है। अपने घर में पानी के रिसाव और उससे होने वाली सीलन को कभी पनपने नहीं देना चाहे घर चाहें नया हो या पुराना उसे सीलन से बचाना जरूरी है और इसके लिए वाटरप्रूफिंग कराना अनिवार्य होता है।

फर्जी खबरों और गुमराह करने वाली सूचनाओं पर रोक लगाएगा फेसबुक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक ने कहा है कि वह फर्जी खबरों और गुमराह करने वाली सूचनाओं पर रोक लगाने का काम शुरू करेगी। भारत समेत कई देशों में फेसबुक पर पोस्ट की गईं फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं के कारण कई हिंसा की वारदातें हुईं। इसके बाद हुई आलोचनाओं को देखते हुए वेबसाइट ने यह कदम उठाने का फैसला लिया है।

फेसबुक अभी सिर्फ उन कंटेंट पर रोक लगाता है, जिनमें सीधे तौर पर हिंसा की अपील की जाती है। हालांकि, नए नियमों में उन फर्जी खबरों और तस्वीरों पर रोक लगाई जाएगी, जिनसे हिंसा भड़क सकती है। फेसबुक पर आरोप है कि वह भारत समेत श्रीलंका और म्यांमार में हिंसा भड़काने में मददगार रहा है।

अमेरिकी वेबसाइट सीनेट के मुताबिक, फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि अफवाह कई तरह से हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अभी भड़काऊ पोस्ट पर रोक लगाई गई है। हम अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, ताकि

फर्जी खबरों को रोक सकें। इसे जल्द लागू किया जाएगा। वहीं, फर्जी खबरों की पहचान को स्थानीय संगठनों से मदद ली जाएगी।

पिछले दिनों फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि वह अपने प्लेटफार्म से फर्जी खबरों को नहीं हटा सकते, लेकिन अगर कोई पोस्ट फर्जी खबरों की तरह दिखाई देती है तो उसे न्यूज फीड में नीचे कर दिया जाएगा। फर्जी खबरें कंपनी के कम्यूनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं करती हैं।

भारत में फेसबुक की मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के जरिये फैली अफवाहों और फर्जी खबरों के चलते कई लोगों की पीट–पीटकर हत्या की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कंपनी से जवाब भी मांगा था।

विदेशों में मौजूद कुल 216 शाखाओं में से 70 शाखाएं बंद होने जा रही हैं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इस साल के अंत तक भारत के सरकारी बैंकों के विदेशों में मौजूद कुल 216 शाखाओं में से 70 शाखाएं बंद होने जा रही हैं। यही नहीं इन 70 शाखाओं के आलावा विदेशों में इन बैंकों की दूसरी सेवाएं भी बंद किए जाने की योजना बनाई गई है।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि विदेशों में बंद की जा रही शाखाओं में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशों की अपनी शाखाओं में भी भारी कटौती करने की योजना बना रहे हैं।

उन शाखाओं को छोड़ कर जो विदेशों में भी प्रॉफिट में हैं उन्हें छोड़कर खाड़ी देशों में जैसे ओमान और दुबई स्थित शाखाओं को भी बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है। बैंक यह कदम खर्चों को कम करने और पूंजी बचाने के लिए कर रहा है। खाड़ी के देशों में भी ये बैंक उन ब्रांचों को बंद करेंगी जिनसे पर्याप्त राजस्व हासिल नहीं हो रहा है।

अधिकारी ने बताया कि इन बैंकों के ब्रांच ने

अपनी गैर मूल संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही इन ब्रांच को कहा गया है कि अपने खर्चों को कम करें। अभी तक 37 ओवरसीज ब्रांच अभी तक बंद किए जा सकते हैं वहीं 60.70 ब्रांच इस साल तक बंद कर दिए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि बंद किए जा रहे ब्रांच पूरी तरह से काम कर रहे थे इन ब्रांच में बैंक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिर और रेमिटेंस ऑफिस भी हैं।

गौरतलब है कि भारत में ही बैंको की लचर व्यवस्था और ढीले रवैये से मोदी सरकार ने कई बार इस पर नीति बनाने की बात की और यह भी चर्चा रही कि समस्त बैंको का पुरा ही प्रारुप बदल कर कुछ ही बैंकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के साथ रखा जाएगा ।

रात को 9 बजे तक खाना खाने वालों को नहीं होती यह जानलेवा बीमारी

यह नई बात नहीं है कि रात को जल्दी खाना खाकर सोने कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं। अक्सर हम यह बात अपने घर में बड़े–बुजुर्गों से सुनते रहे हैं। मगर अब यह बात वैज्ञानिक अध्ययन में भी साबित हुई है।

स्पेन स्थित बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ (आईएसग्लोबल) में हुए अध्ययन में कहा गया है कि रात को 9 बजे के पहले या सोने से 2 घंटे पहले डिनर करने वालों को कई तरह के कैंसर होने की आशंका न के बराबर रहती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि रात का खाना जल्दी खाने वालों को ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका देर से खाना खाने वालों के मुकाबले 20 फीसदी तक कम हो जाती है।

कैंसर के यह दोनों ही प्रकार दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर लोगों में इन दोनों तरह के कैंसर होने की आशंका ज्यादा रहती है। उनका कहना है कि इसके लिए उनके जैविक क्रमचक्र में व्यवधान जिम्मेदार होता है। सोने और जागने की प्रक्रिया बाधित होती है, इसके साथ ही शरीर की अन्य प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने प्रोस्टेट कैंसर के 621 और स्तन कैंसर के 1205 मरीजों के मामलों का अध्ययन किया। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 872 पुरुष और 1321 महिलाओं को औचक तरीके से चुना गया था।

पाकिस्तान चुनाव के मायने

द रीव टाइम्स ब्यूरो (हेम चौहान)

लोकतंत्र की पिच का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में राजनीति का खेल खेलना कोई नई बात नहीं हैं । किंतु यहां बात इसलिए होगी क्योंकि चुनावों ने पाकिस्तान की दिशा और दशा को नया स्वरुप दिया हैं । इस बार के चुनाव पाकिस्तान की असलियत को भी सामने लाए । पाकिस्तान क्रिकेट का बादशाह इमरान खान पाकिस्तान ज़मूहरियत का भी बादशाह बनने का सपना सालों से पाले बैंठा था । इसके लिए साम–दाम–दंड–भेद सभी रणनीतियों पर इमरान ने ज़ोर आजमाईश की । और ये सपना हक़ीक़त में भी सच हो ही गया । किंतु पाकिस्तान ज़मूहरियत कभी भी सच्चाई और क़ायदों व असूलों पर नहीं चला । इसकी चाबी किसी और के पास रहती है और ड्राइवर कोई और ही होता हैं । ऐसा इसलिए भी कहना वाज़िब लगता हैं क्योंकि वहां की सत्ता का संचालन आवाम की मर्ज़ी के बग़ैर आतंक की सान पर दौड़ता रहा हैं ।

इमरान खान भी इससे अलग नहीं हैं । इस बार के इलेक्शन में इमरान खान पर सेना और आईएसआई का सहयोग लेने का

आरोप लगा तो वहीं नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी को जेल से बेल न मिलने का दबाव भी डाला गया जिससे कि इलेक्शन तक वो जेल में ही रहे और बाहर इमरान खान सत्ता तक पंहुच जाए ।

इमरान खान की सेना से जुगलबंदी नई नहीं हैं । परवेज़ मुशरर्फ ने जब पाकिस्तान में तख़्ता पलट किया तो इमरान खान ने खुले तौर पर ज़मूहरियत के ख़िलाफ आवाम के बीच आकर ब्यानबाज़ी की थी और कहा था कि सेना के साथ अब हम सुरक्षित हैं । इस चुनाव में भी दो तरह की बातें खुल कर सामने आई । एक तो इमरान खान को सेना का ऐंजेंट और आईएसआई का समर्थन प्राप्त बताया गया तो वहीं नवाज़ शरीफ को जेल में भी कड़ी प्रतिद्वंदता से देखा जा रहा था क्योंकि उनकी आवाम पर पकड़ आज भी मज़बूत मानी जाती है । चुनावों के परिणामों में यह देखने को भी मिला । इसलिए ही पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने एक नारा यह भी खूब उछाला : भारत का यार– गद्दार गद्दार । नवाज़ के लिए इसी नारे का संबोधन इन चुनावों में था । हालांकि इमरान एक विवादित शक़्सियत रही हैं और उनके अफेयर के किस्से और वैवाहिक जीवन भी गाहे–ब–गाहे चर्चा का विषय बनता रहा हैं । उनकी दूसरी पत्नी ने तो अपनी आत्मकथा में बड़े गंभीर आरोप लगाए । किंतु इमरान बेहद चालाकी और राजनीतिक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट तक पंहुच ही गए ।

इमरान के जीत के मायने हालांकि जमूहरियत में सत्ता पर काबिज़ होने के कुछ समय के बाद ही मालूम पड़ेगी लेकिन कश्मीर पर इमरान का रुख़ बेहद नकारात्मक रहा हैं और बहुत बड़े बड़े वायदों के साथ इमरान ने वोट को अपने हक़ में तबदील किया हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ बोलने के बावजूद मोदी मैज़िक और स्टाईल को ही इमरान खान ने चुनावों में भुनाया हैं । अब देखना दिलचस्प होगा कि नए पाकिस्तान को बनाने का वायदा करने वाले इमरान जन भावनाओं के साथ कितना इंसाफ करते हैं और भारत के साथ किस राह को अपनाने की ज़ोर आज़माईश होती हैं ? क्योंकि आवाम शांति और सद्भाव के साथ ही अपने अधिकार को इस्तेमाल करती हैं..... सत्तासीनों को इस बात से बेख़बर नहीं रहना चाहिए ।

जापानः 40 डिग्री तापमान पहुंचने से जापान में 26 मरे, 12 हजार अस्पताल पहुंचे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जापान में जुलाई महीने का तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच जाने के कारण चली जबरदस्त हीट वेव से अब तक करीब 26 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 बुजुर्ग मौत का शिकार हो गए। इसके अलावा 12 हजार से ज्यादा लोगों को जुलाई माह के पहले दो सप्ताह में ही भयंकर गर्मी से झुलसने के कारण अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है। मौसम विभाग ने अधिकतर क्षेत्रों में तापमान और बदतर स्थिति में पहुंचने की चेतावनी जारी की है।

जापान के आग व आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 15 जुलाई को खत्म हुए दूसरे सप्ताह में 12 लोगों की मौत हीटस्ट्रोक के कारण हुई, जबकि उससे पहले सप्ताह में 3 लोगों की मौत हो गई थी।

क्योडो न्यूज एजेंसी ने बताया कि अकेले शनिवार को 11 बुजुर्ग हीटस्ट्रोक की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में सुधार के कोई संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं।

बच्चे की मौत के बाद स्कूलों को निर्देश जारी

पिछले सप्ताह स्कूल जाते समय हीटस्ट्रोक के कारण 6 साल के एक बच्चे की मौत के बाद शिक्षा मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है। मंत्रालय ने मौसम में सुधार होने तक स्कूलों को आउटडोर गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं।

रिकॉर्ड तोड़ हुआ तापमान

- 233 निगरानी केंद्र बनाए गए हैं देश में तापमान पर नजर रखने के लिए
- 35 डिग्री से ज्यादा का अधिकतम तापमान रविवार को अधिकतर केंद्रों ने दर्ज किया
- 39.8 डिग्री के रिकॉर्ड तापमान को दर्ज किया गया दोपहर बाद गुजो सिटी के मध्य में
- 37 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था टोक्यो के कुछ हिस्सों में दोपहर के दौरान

ऐसा भयानक असर है गर्मी का

- 2700 लोग जुलाई के पहले सप्ताह में हीटस्ट्रोक से अस्पताल पहुंचे
- 9900 से ज्यादा लोगों को दूसरे सप्ताह में अस्पताल लाया गया
- 3091 एंबुलेंस लगानी पड़ी अकेले टोक्यो में शनिवार को
- 01 नंबर पर है ये आंकड़ा किसी एक दिन में एंबुलेंस की नियुक्ति का

2050 तक इलेक्टॉनिक दुनिया में अमर हो जाएगा इंसान

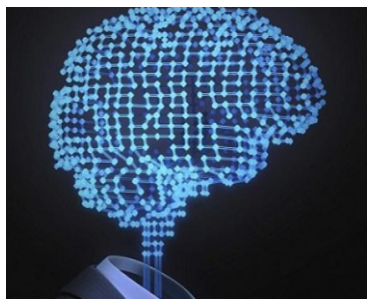

प्रमुख आईटी विशेषज्ञों में से एक डॉ. इयान पियरसन का कहना है कि 2050 तक इंसान एक तरह से अमर हो जाएगा। इंसान का दिमाग तकनीक के साथ इस तरह मिल जाएगा कि उसका शरीर नष्ट होने के बाद भी वह जीवित रह सकेगा। डॉ इयान भविष्यवादी हैं और उनका कहना है कि ऐसा होने पर हमारे मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा।

एंड्रॉयड से जुड़कर अपग्रेडेड शरीर में रहेगा मस्तिष्क

डॉ पियरसन की मानें तो अगले कुछ दशक में इंसान एंड्रॉयड के जरिये जीवित रहेगा। शरीर नष्ट होने के बावजूद हम एक अपग्रेड शरीर में रहेंगे। इस तरह से इंसान अपनी शवयात्रा में भी शामिल होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अमर हो जाएगा। अध्ययन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान की समझ, उसकी याद्दाश्त या एहसास सभी कुछ 2050 तक नई तरह की तकनीक से जुड़ जाएगा।

दिमाग में स्टोर होने वाली हर बात किसी और जगह रहेगी सुरक्षित

इसका मतलब यह हुआ कि इंसान के दिमाग की कॉपी का बैकअप तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी पूरी समझ ही जैविक मस्तिष्क से बाहर किसी अन्य स्थान से संचालित होगी। जैसे हम नेट पर कुछ अपलोड करते हैं, यह ऐसा भी नहीं होगा। दरअसल विशेषज्ञ एक नया प्लैटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जहां से मस्तिष्क काम करेगा। एक दिन इंसान का शरीर खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मगर अब यह कोई समस्या नहीं रहेगा, इनसान का दिमाग 99 फीसदी अच्छी अवस्था में रहता है और यह क्लाउड में आईटी की मदद से बेहतर तरीके से काम करेगा।

इस तकनीक के खतरे भी है

एक निश्चित समय में जब आपको लगे कि आपने काफी डाटा बचा लिया है और आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो किसी एंड्रॉयड सिस्टम से जुड़कर नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तकनीक के लिए क्लाउड पर स्पेस खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत होगी, जिसके लिए टेक कंपनी की मदद लेनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कुछ हद तक जोखिमभरा हो सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने कार्मियों के मस्तिष्क में कैद जानकारी को दूसरे के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए इस स्पेस के जरिये उन्हें अपना गुलाम बना सकती हैं।

चांद पर हुआ करता था एलियन का बसेरा, वैज्ञनिकों का दावा

एलियन को लेकर हमेशा ही शोध सामने आते रहे हैं। लेकिन अब तक यह साबित नहीं हो सका है कि आखिर एलियन थे भी या नहीं । लेकिन हाल ही में एक शोध में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एलियन हुआ करते थे और उनका चांद पर बसेरा हुआ करता था। वैज्ञानिकों को दावा है कि दो अलग–अलग अवधियों के दौरान चांद पर एलियन मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि संभवतरू उल्का पिंडों के ब्लास्ट के कारण एलियनों के रहने के अनुकूल वातावरण पैदा हुआ। जब यह हुआ, तब का वातावरण संभवतरू आज की तुलना रहने योग्य ज्यादा रहा होगा।

ज्वालामुखी विस्फोट से पैदा हुई होगी स्थिति

हालांकि चंद्रमा आज एक धूल और निर्वासित जगह है, विशेषज्ञों का मानना है कि शायद हमेशा ऐसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रहों पर शोध करने वाले दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक संभवतरू चांद पर चार अरब और 3.5 अरब साल पहले जीवन जीने योग्य माहौल था। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह स्थिति संभवतरू 3.5 अरब साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी पैदा हुई होगी । उस वक्त चांद से बड़ी मात्रा में गर्म गैस रिस रही थी। जिस गैस के कारण सतह पर पानी तैयार हुआ।

मैग्नेटिक फील्ड से कवर थी चांद की सतह

वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायॉलजिस्ट डिर्क शुल्ज–माकुच ने कहा, अगर शुरुआती समय में चांद पर लंबे समय के लिए पानी और विशिष्ट वातावरण था, तो हमें लगता है कि चांद की सतह पर अस्थायी रूप से जीवन जीने योग्य माहौल था। शुल्ज ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ग्रह विज्ञान और एस्ट्रोबायॉलजी के प्रफेसर इयान क्राफॉर्ड के साथ मिलकर यह पेपर तैयार किया है। माना जाता है कि चांद की सतह मैग्नेटिक फील्ड से कवर थी जिसने घातक गर्म हवा से किसी भी प्रकार के जीव की रक्षा की होगी।

युगांडाः पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे भारतवंशी- मोदी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतवंशी पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने भारत और रवांडा की मित्रता पर भारतवंशियों द्वारा डाले गए सकारात्मक प्रभावों की प्रशंसा भी की।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने उन्हें पूर्व अफ्रीकी देश में भारतीय समुदाय के कार्यों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि रवांडा में भारतीय समुदाय के साथ खुशगवार बातचीत हुई। भारतवंशी पूरी दुनिया में अपने आप को विशिष्ट साबित कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रवांडा में भारतीय समुदाय से बातचीत करके मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कागमे ने बताया कि भारतीय समुदाय रवांडा के विकास में योगदान कर रहा है और वह बड़े पैमाने पर समाज सेवा करते हैं।

दो दिन के रवांडा के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी युगांडा पहुंचे। प्रधानमंत्री के विमान के एंतेबे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उनकी युगांडा की दो दिन की यात्रा का आगाज हो हुआ । वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही । हवाई अड्डे पर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देशों रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका के पांच दिवसीय दौरे पर गए

युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत और युगांडा का सदियों पुराना रिश्ता है, हमारे बीच श्रम का रिश्ता है, शोषण के खिलाफ संघर्ष का रिश्ता है।

उन्होंने कहा, युगांडा सहित तमाम अफ्रीकी देश भारत के लिए बहुत अहम हैं। इसकी एक बड़ी वजह यहां बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने गुलामी के खिलाफ साझा संघर्ष किया है। फिर हम सभी के सामने विकास की समान चुनौतियां हैं।

उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए लोगों को कहा कि मुमकिन है कि बहुत जल्द यहां युगांडा में आपको मेड इन इंडिया के लेबल वाला स्मार्टफोन नजर आए। मोदी ने कहा कि वह दूसरी बार युगांडा आए हैं। इससे पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यहां आए थे।

रवांडा को 1377 करोड़ रुपये का कर्ज देगा भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी देश रवांडा को 20 करोड़ डॉलर (1377 करोड़ रुपए) का कर्ज देने को मंजूरी दी है। रवांडा को औद्योगिक पार्क और किगाली सेज विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर तथा कृषि क्षेत्र के लिए 10 करोड़ डॉलर (कुल 20 करोड़ डॉलर) की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई है। मोदी ने कहा कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत रवांडा की आर्थिक प्रगति में उसके साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहां ग्रामीण विकास और छोटे उद्योगों में बहुत अवसर मौजूद हैं। गौरतलब है कि रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे तेजी से विकसित हो रहा देश है।

दूतावास खोलने का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान में रवांडा की राजधानी किगाली में भारतीय दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा इससे दोनों देशों की संबंधित सरकारों के बीच न सिर्फ संवाद स्थापित होगा, बल्कि वाणिज्य संबंधी, पासपोर्ट, वीजा के लिए सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। मोदी ने कहा कि वर्षों से भारतीय समुदाय रवांडा में उच्च आयोग की स्थापना चाहता था। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत–रवांडा के संबंध हर धूप–छांव झेल चुका है।

रक्षा और कषि समेत आठ क्षेत्रों में समझौता

इससे पहले पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे से 30 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान दोनो नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, पशु संसाधन, डेयरी, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लेदर और कृषि जैसे आठ क्षेत्रों में सहयोग करने को लेकर समझौते हुए।

अमेरिकी विश्वविद्यालय को भारतीय दंपत्ति ने किया 1,20,00,000 डॉलर का दान

फ्लोरिडा में एक भारतीय अमेरिकी दंपति ने अमेरिकी विश्वविद्यालय को कॉलेज की स्थापना के लिए एक करोड़ 20 लाख डॉलर की राशि दान दी है।

साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने एक बयान में बताया है कि पटेल कॉलेज ऑफ ग्लोबल सस्टेनिबिलिटी की स्थापना के लिए किरन सी और पल्लवी पटेल ने एक करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर का दान दिया है।

अभियंत्रिकी, उद्यमियों और पूरे दुनिया में पर्यावरण प्रबंधकों द्वारा परियोजनाओं के लिए शहरी प्रणालियों में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करने और परियोजनाओं के विस्तार, जल संसाधन एवं उपयोग और परिवहन के लिए 2010 में यहां पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। इस परियोजना से कॉलेज के स्तर के उन्नयन के साथ ही इसे मजबूती भी मिलेगी।

मलाओस में टूटा बांध, सैकड़ों लोग लापता, कई के मरने की आशंका

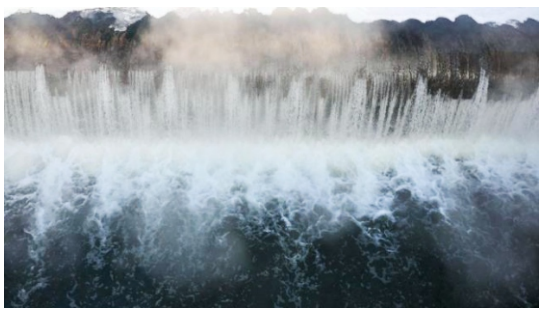

दक्षिण–पूर्वी लाओस में पनबिजली परियोजना से संबंधित एक निर्माणाधीन बांध के ढह जाने से छह गांव जलमग्न हो गए। इस घटना के बाद से सैकड़ों लोग लापता हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के मरने का अंदेशा है। लाओस की सरकारी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी। गरीब और चारों तरफ से जमीन से घिरे वामपंथी देश लाओस में नदियों का व्यापक संजाल है। इनमें से कई नदियों पर पनबिजली बनाने के लिए बांध बनाए गए हैं और कई पर बनाए जाने की योजना है।

लाओस इन बांधों के जरिये उत्पादित अधिकतर पनबिजली थाईलैंड जैसे अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। लाओस न्यूज एजेंसी ने बताया कि बांध ढहने की घटना दक्षिण–पूर्वी अत्तापु प्रांत के सनामक्से जिले में हुई। इससे करीब पांच अरब घनमीटर पानी बहकर पास के गांवों में पहुंच गया, जिससे वहां अचानक बाढ़ आ गई और वे जलमग्न हो गए। बांध से निकला पानी ओलंपिक खेलों के 20 लाख तरण तालों के पानी के बराबर होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मरने की आशंका है। कई मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि लापता या मारे गए लोगों की कोई अधिकारिक संख्या फिलहाल प्रशासन ने घोषित नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार, अत्तापु प्रांत के प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मूलभूत मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की है।

यह बांध 1.2 अरब डॉलर की एक परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना वियनतियाने की जे पियान जे नाम्नोय पॉवर कंपनी (पीएनपीसी) की है, जो 2012 में तैयार की गई थी। इस परियोजना में थाईलैंड की राचबरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटिंग होल्डिंग, दक्षिण कोरिया की कोरियन वेस्टर्न पॉवर और लाओस की सरकारी लाव होल्डिंग स्टेट इंटरप्राइज जैसी कई कंपनियां शामिल हैं।

राचबरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटिंग होल्डिंग ने कहा कि लगातार बारिश होने की वजह से बांध ढहा। बांध ढहने की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री थोंग्लोन सिसोलिथ ने सरकारी बैठकें रोक दीं। वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की निगरानी के लिए प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे।

भारत में एचआईवी संक्रमण पर आई ताजा रिपोर्ट, जानें कम हुआ या बढ़ा है खतरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामले, एड्स के कारण मौत और एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2010 से 2017 के बीच घटी है। इसका श्रेय सतत एवं केंद्रित प्रयास को जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

एड्स पर संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त एजेंसी (यूएनएड्स) की 'माइल्स टू गो–क्लोजिंग गैप्स, ब्रेकिंग बैरियर्स, राइटिंग इन्जस्टिसेज' नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों ने एचआईवी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्ष 2010 से 2017 के बीच आबादी तक पहुंच के सतत और केंद्रित प्रयासों के चलते कम्बोडिया, भारत, म्यामां, थाईलैंड और वियतनाम में एचआईवी संक्रमण के मामलों मे उल्लेखनीय कमी आई है।

हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर एचआईवी के नए संक्रमणों में उतनी तेजी से कमी नहीं आ रही। इसके अलावा पाकिस्तान और फिलीपीन में यह संक्रमण फैल रहा है।

भारत में वर्ष 2010 में एचआईवी संक्रमण के 1,20,000 मामले थे जो वर्ष 2017 में घटकर 88,000 रह गए।

इसी अवधि में एड्स के कारण होने वाली मौत 1,60,000 से घटकर 69,000 रह गई जबकि एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 23,00,000 से घटकर 21,00,000 रह गई। इसमें कहा गया कि भारत ने विशेष सुरक्षा रणनीति, नीति या रूपरेखा बनाई और इसे लागू किया।

सफलता की मिसाल: क्लास टीचर ने कहा था- जेल में कटेगी जिंदगी, पर बन गए अरबपति

ज्यादातर लोगों का मानना है कि सफलता की प्रथम और मुख्य सीढ़ी है शिक्षा। लेकिन आज शिक्षा का हाल ऐसा है कि एमए और पीएचडी धारक भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने से नहीं हिचकते।

आज 10वीं, 12वीं में कोई छात्र यदि अच्छे अंक नहीं ला पाता तो उसके मां–बाप को लगता है कि उनका बेटा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो बच्चों रिजल्ट खराब होने पर इतनी ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं कि बच्चे आत्महत्या तक कर बैठते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि आज के जमाने में भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो 10वीं फेल होने या पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी अरबपित बने हैं।

10वीं से पढ़ाई छोड़कर सफल व्यक्ति बनने वाले लोगों में से एक 'वर्जिन ग्रुप' के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन भी हैं। रिचर्ड ब्रांसन आज अरबपति व्यक्ति हैं और उनके वर्जिन ग्रुप में 400 कंपनियां हैं और हजारों लोग उनकी नौकरी करते हैं। आगे जानें पढ़ाई छोड़ने के बाद भी ब्रांसन कैसे बने अरबपति–रिचर्ड ब्रांसन के तीसरे दादा 1793 में भारत आए थे तो इस दौरान ब्रांसन के पिता भी मद्रास आ गए। यहां कुछ समय तक रहने के बाद उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी की जिससे रिचर्ड ब्रांसन का जन्म हुआ।

रिचर्ड जब कुछ बड़े हुए तो उनके पैरेंट्स ने लंदन स्टोव स्कूल में पढ़ने भेज दिया। लेकिन उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी होने के कारण वह ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। इससे ज्यादा मुश्किल तो तब हो गई जब क्लास में उनकी पहचान एक मंदबुद्धि छात्र में रूप में बन गई। अब रिचर्ड का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में न लगता ।

रिचर्ड का पढ़ाई में मन न लगने के कारण एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि उनकी सारी जिंदगी जेल में बीतेगी अगर वह पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें तो कुछ और ही करना था। उन्होंने 10वीं पास करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और एक चर्च की मैगजीन में सहयोग करने लगे। यहां उनकी बड़े लोगों से पहचान बनी और उन्होंने म्यूजिक सीडी की खुद की दुकान खोल ली। इस दुकान का विज्ञापन जब उन्होंने अपनी चर्च की मैगजीन पर दिया तो इसका ऐसा असर हुआ कि वह रातों–रात एक बड़े कारोबारी बन गए।

उनका धंधा इतना तेजी से बढ़ा कि उन्होंने एक और दुकान खोली और इसका नाम रखा वर्जिन। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके पास वर्जिन एयरलाइन्स समेत कई कंपनियां हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। 2006 में संडे टाइम्स की ओर से जारी यूरोप के 1000 अमीर लोगों की लिस्ट रिचर्ड ब्रांसन नाम टॉप टेन अमीर लोगों में शुमार था।

ऊंचे स्वर में पढ़ने से बढ़ती है याददाश्त : अध्ययन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अगर आपका बच्चा कोई पाठ याद नहीं कर पा रहा है तो उसे ऊंचे स्वर में पढ़ने की आदत डालने को कहिए । एक अध्ययन में पता चला है कि जोर से पढ़ने से लंबी अवधि की याददश्त बढ़ती है। अध्ययन के नतीजों में सामने आया है कि बोलने और सुनने की दोहरी कार्यविधि उत्पादन प्रभाव का याददाश्त पर लाभकारी असर होता है । बोलने और सुनने से शब्द जाना–पहचाना बन जाता है और इस प्रकार उसके मस्तिष्क में प्रति धारण यानी स्मृति में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।

कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोलिन एम. मैकलियोड ने कहा अध्ययन में सक्रिय सहभागिता से सीखने और स्मृति के फायदे की पुष्टि होती है। उन्होंने आगे बताया जब हम सक्रिय उपाय या उत्पादन तत्व किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो वह शब्द ज्यादा विशिष्ट बनकर हमारी लंबी अवधि की स्मृति में रहता और वह स्मरणीय बन जाता है। मेमोरी नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में शामिल दल ने लिखित सूचनाओं को सीखने की चार विधियों का परीक्षण किया, जिनमें शांत होकर पढ़ना, किसी को पढ़कर सुनाना, अपने पढ़े हुए को रिकॉर्ड करके सुनना और जोर से पढ़ना शामिल था।

अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि जोर से पढ़ने का जो उत्पादन प्रभाव है, वह याददाश्त के लिए सबसे अच्छा है। मैकलियोड ने बताया अध्ययन बताता है कि कार्य करने के विचार या क्रियाशीलता भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। यह अनुसंधान पूर्व के अध्ययनों पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि गतिविधियों का उत्पादन प्रभाव जैसे– शब्द लिखना और टाइप करना, से आखिरकार स्मृति बढ़ती है।

डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए जरूर खाएं ये 5 सुपरफूड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डिप्रेशन या अवसाद ऐसी समस्या है, जिसका समय रहते पता न चले तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। इस बीमारी का संबंध दिमाग में सूजन या हलचल से होता है। मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए दिमागी उत्तेजना को शांत रखना जरूरी है। इसके लिए पोषक आहार बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी को अपने पास फटकने से रोकना चाहते हैं, तो ये 5 सुपरफूड आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से लेने से न सिर्फ डिप्रेशन को दूर रखने में मदद मिलती है, बलकि यह एंटी डिप्रेसेंट गोलियों के रूप में लिए जाने वाले सेरोटोनिन हॉर्मोन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सलाद पत्ता सामान्य कोशिकाओं को विषाक्त या टॉक्सिक होने से बचाता है। इससे ब्रेन डैमेज और शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारी पनपने की आशंका कम होती है। साथ ही इनमें मौजूद विटामिन ए, सी, ई और के के अलावा आयोडीन, मैग्नीशियम भी होता है। यह फाइटोन्यूट्रिएंट से भी लैस होते हैं, जो रोजाना हमारे दिमाग की सुरक्षा करते हैं। इन सबजियों में मौजूद प्रो और प्री बायोटिक्स पेट को भी दुरुस्त रखते हैं और दिमाग की समय–समय पर मम्मत भी करते रहते हैं।

फल

फलों में भी काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। खासतौर से सेब में फाइबर होने के साथ ही यह आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। डायबिटीज के मरीज रोज एक सेब आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसका जीआई काफी कम होता है। इसके अलावा सामान्य लोग दूसरे फल भी आराम से खा सकते हैं क्योंकि ज्यादातर फलों में विटामिन, मिनरल के अलावा प्राकृति मिठास होती है, जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती है।

बीज

हमारे खाने में बीजों का भी अहम रोल है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का शाकाहारी स्रोत होते हैं। इनमें मौजूद गुड फैट फलों और सबजियों के साथ खाने पर उनमें मौजूद सुरक्षा करने वाले पौषटिक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं। इस तरह यह अलजाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से दिमाग की रक्षा करते हैं।

अखरोट

इसी बनावट भी दिमाग की तरह लगती है। हमारा दिमाग 80 फीसदी फैट से बना है, इसलिए यह बच्चों और बड़ों के सुबह के नाश्ते को पूरा करने की सबसे अहम चीज है। यह मूड सुधारता है और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के कामकाज में मदद करते हैं। साथ ही यह डिप्रेशन के लक्षणों को भी रोकता है।

प्याज

प्याज में इतने गुण होते हैं कि इसे कई बार बीमार का मददगार भी कहा जाता है। यह सलाद और सब्जी में खाया जाता है। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह कैंसर की रोकथाम में और आपका मूड अच्छा बनाए रखने में अहम रोल निभाता है।

चीन के बढ़ते दखल को लेकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत-यूएस बढ़ाएंगे सैन्य सहयोग

भारत–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व मुक्त नेविगेशन के लिए अमेरिका भारत सहित 'क्वाड' में शामिल देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए बड़ी कवायद कर रहा है। भारत, आस्ट्रेलिया व जापान के साथ हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद पर रोकथाम, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे और स्वतंत्र व मुक्त नियम आधारित व्यवस्था के लिए साझा तंत्र बनाने की दिशा में अमेरिका गंभीरता से काम कर रहा है।

अमेरिका ने चतुष्कोणीय सहयोग (क्वाड) को नेशनल डिफेंस अथराइजेशन एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। अमेरिका की मंशा है कि इस क्षेत्र में साझा क्षेत्रीय आधारभूत ढांचा तैयार हो। चारों देश मिलकर इस क्षेत्र में सैन्य सहयोग, साझा अभ्यास, क्षमता निर्माण के लिए काम करेंगे। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए अमेरिका के प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वर्चस्व की होड़

अभी तक यह माना जा रहा था कि क्वाड केवल असैन्य गतिविधियों, कूटनीतिक पहल व दबाव के लिए काम करेगा। लेकिन अमेरिका का प्रस्ताव क्षेत्र में बर्चस्व की होड़ में प्रभावी कदम साबित हो सकता है। क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान शामिल हैं। अन्य देशों से भी सहयोग बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि भारत–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग चीन के खिलाफ नहीं है। समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था के लिए भारत वकालत करता रहा है। आसियान देशों से भी भारत का सहयोग इसी सोच पर आधारित है।

चीन को संदेश

रायसीना डॉयलाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ मिलकर काम करने की मंशा जाहिर की थी। इसका चीन ने स्वागत भी किया था। लेकिन कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि दरअसल चतुष्कोणीय सहयोग चीन को संदेश है। अमेरिका का प्रस्ताव चीन की चिंताओं को और बढ़ा सकता है।

जानकार बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं

जानकार मानते हैं कि भारत का अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग भले ही सीधे चीन पर केंद्रित नहीं हो, लेकिन इस क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश निश्चित रूप से बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। भारत में कूटनीतिक हलकों में यह राय उभरकर आई है कि सेना से ज्यादा नौसेना का साझा प्लेटफार्म पर विस्तार करने की जरूरत है।

शक्ति संतुलन साध रहा भारत

सूत्रों ने कहा कि दुनिया में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए भारत एशिया में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा है। चीन भारत के प्रभुत्व वाले इलाकों में अपना बर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वहीं भारत भी सहयोगी देशों के साथ शक्ति सुतंलन में जुटा है। क्वॉड को इसके लिए बड़ा मंच माना जा रहा है।

शौर्य दिवस: भयानक था वह मंजर... शरीर के पार होते थे बम के स्प्लिंटर

करगिल युद्ध में पूर्वांचल के जांबाज सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई। उनमें से एक हैं बीआरडी मेडिकल कालेज के रेडियोथेरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष मेजर डॉ. एमक्यू बेग। उन दिनों डॉ. बेग सेना की तीन पंजाब यूनिट में बतौर रेजीडेंट मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। यह यूनिट बटालिक की 15 हजार फीट उंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभाले हुए थी ।

कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक में तैनात थे मेजर डॉ. एमक्यू बेग

बटालिक में पहाड़ की कई चोटियां हैं। पाकिस्तान के सैनिक ऊंची चोटियों पर थे और भारतीय सैनिक नीचे की चोटियों पर। इसके कारण पाकिस्तानी मशीनगन के साथ ही ग्रेनेड से गोलीबारी कर रहे थे। बम धमाके के दौरान निकलने वाले छर्रे(स्प्लिंटर) सैनिकों को ज्यादा घायल करते। लड़ाई के दौरान चार डॉक्टरों पर सैनिकों के इलाज का जिम्मा रहा। बमों के छर्रे से रोजाना दर्जनों सैनिक घायल होते। सुरक्षा के लिए बने छोटे नालों में घायल सैनिकों को लिटाकर इलाज किया जाता था। ब्रिगेडियर ने आतंकियों के खात्मे के लिए कर्नल के नाम पर ही इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा।

Advertorial

मिशन रीव - रोजगार और करियर का बेहतरीन विकल्प

मिशन रीव की यात्रा- और करियर के अवसर

मिशन रीव (रूरलाइजिंग इंडिया –एंपावरिंग विलेजिज़) का उदभव अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति सिद्धांत पर हुआ। इसके तहत ग्रामीण समाज में रहने वाले व्यक्तियों विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना, ज्ञान तथा कौशन की मांग गांवों में रह रहे शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवाएं प्रदान कर की जा रही है। यह न केवल गांवों में रोजगार के लिए प्रभावी विकल्प है अपितु ग्रामीण परिवेश में विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यस्था को सुदृढ़ कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग से हजारों लोगों को अपने ही गांव में अपने लोगों के लिए काम कर रोजगार प्रदान करने वाला यह एक अनूठा प्रयास है।

जून 2017 में मिशन की रूपरेखा तैयार की गई। जुलाई 2017 में इसे आईआईआरडी बोर्ड द्वारा अधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगस्त और सितंबर में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई । सितंबर 2017 में आधारभूत प्रारंभिक प्रशिक्षण का प्रयास किया गया । 30 सितंबर 2017 को केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज व कृषि परषोत्तम रूपाला द्वारा मिशन का विधिवत शुभारंभ किया गया। अक्तूबर 2017 को विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया। 26 फरवरी 2018 को हिमाचल के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री श्री विरेंद्र कंवर ने आईआईआरडी में स्वास्थ्य स्लेट ,मोबाईल लैब, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक छिड़काव आदि सेवाओं का शुभारंभ किया। 16 जुलाई 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री बीके अग्रवाल ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के अंतर्गत जैनरिक मेडीसन आउटलैट का शुभारंभ किया ।

मिशन रीव द्वारा अभी तक दी जा रही सेवाओं का सारांश

स्वास्थ्य डिविजन

सेवाएँ	अब तक	1 साल मे लक्ष्य
स्वास्थ्य स्लेट	15000 लोगों तक पहुँच	10 लाख लोग लक्ष्य
मोबाइल लैब	3000 लोगों तक पहुँच	10 लाख लोग लक्ष्य
जनऔषधि स्टोर	3 जिलों मे 5 स्टोर खुले	300 स्टोर का लक्ष्य
टेलीमेडिसिन	आईटी इंटरफेस तैयार	10 लाख लोग लक्ष्य

जैविक खेती डिविजन

सेवाएँ	अब तक	1 साल मे लक्ष्य
जैविक खाद	2 लाख किलो	50 लाख किलो
जैविक अवशिष्ट अपघटक	50000 लीटर	10 लाख लीटर
मिट्टी की जांच	9 मिट्टी जांच लैब स्थापित	10 लाख किसान
उच्च गुणवत्ता के बीज	3 जिला मे 1200 लोगों तक	10 लाख लोग लक्ष्य
दुधारू पशु जैविक फीड	1000 किलो 1200 लोगों तक	10 लाख लोग लक्ष्य
मशरूम खेती	लैब स्थापित	4 हजार मेम्बर लक्ष्य

सेवा सहायता सदस्यता

सेवाएँ	अब तक	1 साल मे लक्ष्य
सरकारी सेवा सुविधाएं	4000 मेम्बर्स रजिस्टर्ड	1 लाख लोग लक्ष्य
गैर सरकारी सेवा सुविधाएं		
निजी/विशेष सेवा सुविधाएं		
उपभोक्ता वस्तु विक्रय	5 हजार लोगो तक पहुँच	10 लाख लोग लक्षय

बैंकिंग डिविजन

सेवाएँ	अब तक	1 साल मे लक्ष्य
बैंकिंग	निधि कंपनी स्थापित	10 लाख लोग लक्ष्य
इन्शुरेंस	LIC से अनुबंध	10 लाख लोग लक्षय
वित्तीय ऋण	वित्तीय संस्थानो से अनुबंध	10 हजार लोग लक्ष्य

इन सभी प्रकार की सेवाओं को शुरु करने के लिए मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां करने की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में है तथा शीघ्र ही समूचे प्रदेश से आवेदन आमंत्रित किए जाएगें । गाँव के हर घर तक पहुँचने के लिए मिशन रीव को जरूरत है ऐसे युवाओं की जो अपने गाँव मे रहते हुए गाँव को बेहतर बनाने के लिए काम कर सके ।

ऐसे युवा जिन्हें ग्रामीण समस्याओं की जानकारी हो तथा समाधान के लिए प्रयास करने की लग्न हो, जो अपने गांवों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए अथक श्रम एवं सेवा भाव से काम कर सकें ।

आवश्यक योग्यताएं :

10वीं न्यूनतम,
बेसिक कंप्यूटर / नेटवर्क शिक्षित
कम्यूनिटी मोबेलाइजेशन क्षमता

कार्य क्या करना होगा :

- अपनी पंचायत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाना जैसे : स्वस्थ्य सुविधाएं हासिल करने मे सहायता आदि।
- सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को प्राप्त करने मे सहायता ।
- जैविक खेती, कृषि संबंधी, मिट्टी जांच संबंधी हर सुविधा को हासिल करने मे सहायता ।
- पशु पालन मे जैविक दुग्धवर्धक, पशु स्वास्थ्य वर्धक फीड सप्लीमेंट उपलब्ध करवाने मे सहायता।
- मिशन द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा सेवाओं की जानकारी घर द्वार तक पहुंचा कर सेवाओं को लेने के लिए सदस्यता पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करना ।
- मिशन रीव द्वारा संचालित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और ग्रामीण लोगों की जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए सेवाओं को देना ।
- ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों तथा महिला मण्डल, युवक मण्डल जैसे सामुदायिक समूहों के साथ एक गतिशील संपर्क एवं संवाद स्थापित करना ।
- राजस्व उत्पादन के लिए लोगों /सदस्यों को सेवाएं प्रदान करके मिशन को सफल बनाने के लिए योजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत मे मिशन के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करके मिशन को अधिक व्यवहार्य, लाभदायक, प्रभाव–उन्मुख और स्वावलंबी बनाना।
- मिशन रीव के HQ के अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रकार के संवादों का आदान प्रदान रपटों तथा सूचनाओं का रखरखाव एवं साझा करना।
- पंचायत स्तर पर सम्पन्न की गईं दैनिक गतिविधियों को समय पर पूरा कर उच्च अधिकारियों को आवधिक रिपोर्ट जमा करना।

आने वाली सेवाओं का सारांश

सेवाएँ	सम्बंधित कार्य
संपत्ति प्रबन्धन डिवीजन	जमीन सबंधंत कार्य : रजिस्ट्रेशन, डिमार्केशन, मैप अप्रूवल, क्रेय–विक्रय सहयोग आदि
उद्यमिता तथा व्यवसाय प्रबन्धन डिवीजन	उद्यम का चयन : परियोजना रिपोर्ट, वित प्रबन्धन, एक वर्ष तक सलाहकार सहयोग, लघु उद्योग प्रोत्साहन
शिक्षा तथा प्रशिक्षण डिवीजन	नईतकनीक का समावेश : सुनिश्चित रोजगार, आधारित प्रशिक्षण, अग्रिम जीवन कौशल प्रशिक्षण
आयात – निर्यात डिवीजन	जैविक उत्पादों के क्रय विक्रय में सहयोग, कृष्कों से उत्पादकों व लघु उद्योगों को आयात निर्यात
शोध एवं विकास डिवीजन	विकास को तीव्र गति प्रदान करने शोध तथा विकास पर कार्य
मुद्रण एवं प्रकाशन डिवीजन आदि	द रीव टाइम्स के अतिरिक्त विभिन्न प्रकाशनों को प्रोत्साहित करना

दैनिक कार्यकलाप

कार्य	फ्रिक्वेन्सी	कुल दिवस
पंचायत के 3 लोगों से मिल कर मिशन रीव की सेवाओं बारे पूरी जानकारी देना, तथा उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना।	हर दिन	23 दिन
पंजीकृत सदस्य से मिलना उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना।	हर दिन	23 दिन
महिला/युवक मण्डल से मीटिंग कर मिशन रीव की सेवाओं बारे पूरी जानकारी देना	महिने में एक दिन	1 दिन
पंजीकृत सदस्यों से बैठक मीटिंग कर उनसे सेवाओं बारे फीडबेक लेना	महिने में एक दिन	1 दिन
पंचायत मे सभी प्रकार की सेवा मांग की आपूर्ति करना	हर दिन	23 दिन
पंचायत मे सेवाओं की मांग संभावना तलाशना	हर दिन	23 दिन

आवेदन सम्बंधित जानकारी :

मिशन रीव की वैबसाइट www.missionriev.in के Recruitment सेक्शन मे जा कर आवेदन से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है ।

चयन प्रक्रिया की रूपरेखा शीघ्र तय कर www.missionriev.in में उपलब्ध होगी। चयनित उम्मीदवारों को NSDC से सम्बद्ध 30 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं के खर्चे पर पूरा करना होगा। इसका पूरा विवरण मिशन की वैबसाइट पर उपलब्ध होगा।

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

रोजगार के लिए आवेदन तथा रिक्तियों संबंधी जानकारी लेने के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर तथा ईमेल पर संपर्क करें :–
0177– 2640761, 2844073 surender@iirdshimla.org info@iirdshimla.org hr@iirdshimla.org